कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत कृषि अखबार

Registered Postal Regn. No.MP/Bhopal/143/2025-27 RNI No. 1832/57 डाक प्रेषण का दिन - सोमवार, मंगलवार

# कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार

भोपाल-जयपुर-रायपुर ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 भोपाल, प्रकाशन - सोमवार, 16 फरवरी 2026 वर्ष - 80 अंक - 25 मूल्य - रु. 12/- कुल पृष्ठ -16 www.krishakjagat.org पृष्ठ- 1

**भारत-अमेरिका व्यापार समझौता**

# किसानों के लिए अवसर या चुनौती?

देश के 85त्न किसान छोटे और सीमांत हैं। समझौते का सीधा असर इन्हीं पर पड़ेगा।

● मधुकर पवार, मो.: 8770218785

भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर देश में बहस तेज है। सरकार इसे ऐतिहासिक अवसर बता रही है, जबकि किसान संगठन और विपक्ष संभावित नुकसान को लेकर चिंतित हैं। समझौते के कृषि अध्यायों की जटिलताएं छोटे किसानों में चिंता पैदा कर रही हैं। इस लेख में हम इस व्यापार समझौते से जुड़े संभावित खतरों, आशंकाओं और समाधान पर चर्चा करेंगे।

– संपादक

## समझौते के प्रमुख बिंदु

- टैरिफ में छूट और आयात-निर्यात कोटा
- सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी मानक
- बौद्धिक संपदा अधिकार और कृषि सब्सिडी
- संवेदनशील फसलों की सुरक्षा

## सरकार का पक्ष

- निर्यात बढ़ेगा
- निवेश और तकनीक आएगी
- संवेदनशील फसलों की सुरक्षा का दावा

**‘ एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी किसान को एक साल में 50 लाख रूपये तक सब्सिडी मिलती है वहीं भारत के किसानों को सालाना 40 हजार रूपये की सब्सिडी मिल पाती है। ’**

इन दिनों भारत सरकार और विपक्षी दलों के बीच भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौता को लेकर विवाद चल रहा है। व्यापार समझौते को सरकार ‘ऐतिहासिक अवसर’ बताकर पेश कर रही है जबकि विपक्षी दलों के साथ देश के विभिन्न किसान संगठन भी इस समझौते का विरोध कर रहे हैं।

### किसानों की शंकाएं

केंद्रीय मंत्रियों के असंतोषजनक और अस्पष्ट जवाब से विपक्षी दलों और किसान संगठनों की आशंका को बल मिल रहा है कि यह समझौता किसानों के हित में नहीं है। सरकार का दावा है कि अमरीका के साथ व्यापार समझौता भारतीय कृषि उत्पादों के लिए बड़े बाज़ार खोलेगा, निर्यात बढ़ेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और आधुनिक तकनीक व निवेश भारत आएगा। आधिकारिक बयान यह भी दोहराते हैं कि किसी भी संवेदनशील फसल या किसान हितों से समझौता नहीं किया गया है।

### आयात निर्यात कोटा और संभावित चुनौती

लेकिन समझौते के कृषि अध्यायों की बारीकियाँ जैसे टैरिफ में छूट, आयात-निर्यात कोटा, सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी मानक, बौद्धिक संपदा अधिकार और कृषि सब्सिडी किसानों के बीच चिंता पैदा कर रही हैं। देशभर के किसान संगठनों का कहना है कि अमरीकी कृषि प्रणाली बड़े पैमाने पर सब्सिडी, अत्याधुनिक मशीनरी और कॉरपोरेट-आधारित उत्पादन पर टिकी है। ऐसे में यदि अमरीकी कृषि उत्पाद सस्ते दामों पर भारतीय बाज़ार में प्रवेश करते हैं, तो छोटे और सीमांत किसान प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएँगे।

### डेयरी उत्पादों पर असर

मक्का, सोयाबीन, कपास, डेयरी और बागवानी उत्पादों में आयात बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अमरीका में डेयरी उत्पादन पर भारी सरकारी सहायता और बड़े फार्मों का दबदबा है। किसान संगठनों का तर्क है कि इससे भारत के करोड़ों छोटे किसानों और डेयरी से जुड़े लोगों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है।

( शेष पृष्ठ 2 पर )

- 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत
- न्यूनतम समर्थन मूल्य सुरक्षा की आवश्यकता
- भावांतर जैसी योजना से नुकसान की भरपाई
- आयात प्रभावित फसलों के लिए मुआवज़ा

कृषक जगत न्यूज़ वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें

अंदर पढ़िये...

5

फसलों की गहाई एवं सुरक्षा के उपाय

### हर FTA में किसानों का हित सर्वोपरि

# प्रमुख फसलें व डेयरी-पोल्ट्री सुरक्षित : श्री चौहान

## IARI का 64वां दीक्षांत समारोह

**नई दिल्ली (कृषक जगत)।** केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत द्वारा किए गए सभी मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में किसानों और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली के 64वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।

**प्रमुख फसलें, डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र सुरक्षित:** केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाल के व्यापार समझौतों में गेहूँ, मक्का, चावल, सोयाबीन और मोटे अनाज जैसी प्रमुख फसलों के हितों को संरक्षित रखा गया है। डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के संबंध में भी किसानों के हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

**'विकसित भारत 2047' में कृषि की केंद्रीय भूमिका:** श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में 'विकसित कृषि और समृद्ध किसान' आधारशिला हैं। कृषि को उन्होंने अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बताते हुए कहा कि यह करोड़ों परिवारों की आजीविका, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का आधार है।

**'लैब टू लैंड' पर जोर:** केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 'लैब टू लैंड' की अवधारणा को साकार करना प्रत्येक वैज्ञानिक की जिम्मेदारी है, ताकि शोध प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकें खेतों तक पहुंचें और किसानों की आय में वृद्धि हो। इस वर्ष कुल 470 विद्यार्थियों को उपाधियाँ प्रदान की गईं, जिनमें 290 एम.एससी./एम.टेक. और 180 पीएच.डी. छात्र शामिल हैं।

## भारत-अमेरिका व्यापार समझौता... (पृष्ठ 1 का शेष)

**स्पष्टता की कमी और मंत्रियों के जवाब**- सरकार के सभी मंत्री अमेरिका के साथ हुए समझौते को ऐतिहासिक समझौता करार देते हुए कह रहे हैं कि 'किसानों के हित सर्वोपरि हैं' तथा किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया है लेकिन समझौते के ठोस बिंदुओं पर स्पष्टता नहीं कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पाते। कई बार बयान सामान्य आश्वासनों तक सीमित रह जाते हैं, जैसे 'कोई नुकसान नहीं होगा' या 'सभी हितधारकों से चर्चा की गई है।' यही कारण है कि मंत्रियों के जवाबों से किसान संगठन भी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस समझौते को 'किसान विरोधी' और 'कॉरपोरेट-परस्त' करार दिया है। उनका कहना है कि यह समझौता अमरीकी दबाव में किया गया है। विपक्षी के मुताबिक जब देश में पहले से ही कृषि संकट, किसानों पर कर्ज़, जलवायु परिवर्तन और बाज़ार अस्थिरता जैसी समस्याएँ हैं, तब अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का बोझ किसानों पर क्यों डाला जा रहा है?

**छोटे किसानों को नुकसान**- भारत की कृषि संरचना असमान है। देश के करीब 85 प्रतिशत और सीमांत किसान हैं। इनके पास न तो भंडारण की क्षमता है, न ही अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक सीधी पहुँच। व्यापार समझौते से संभावित निर्यात लाभ मुख्यत: बड़े किसानों, एग्री-प्रोसेसिंग कंपनियों और निर्यातकों को मिल सकता है। जबकि आयात बढ़ने का सीधा असर छोटे किसानों पर पड़ेगा। यहां यह भी ध्यान देना होगा कि अमेरिका में किसानों और डेयरी उद्योगों को भारी सब्सिडी दी जाती है और जब अमेरिका से कृषि और डेयरी उत्पाद भारत के बाजार में आयेंगे तो निश्चित ही उनकी कीमतें भारत के किसानों द्वारा उत्पादित कृषि और डेयरी उत्पादों से कम होंगी। ऐसी स्थिति में विशेषकर लघु और सीमांत किसानों के सामने वृहद संकट खड़ा हो सकता है। जब समझौते पर मुहर लग जाएगी तब सरकार भी इससे पीछे नहीं हट सकती।

**आगे की राह**- अभी केवल किसान संगठनों द्वारा ही विरोध किया जा रहा है। सरकार के सामने अभी यही सही अवसर है जब वह किसानों को इस समझौते के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करे। समझौते के प्रावधानों को सार्वजनिक किया जाए और राज्यों व किसान संगठनों के साथ पारदर्शिता के साथ चर्चा कर कोई सर्वमान्य समाधान निकाले। सरकार को यह भी लिखित में आश्वासन देना होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी और सब्सिडी जारी रहेगी तथा इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लघु और सीमांत किसानों को विशेष संरक्षण भी देना होगा तथा इसके तहत मध्यप्रदेश में चलाई जा रही भावांतर योजना की तर्ज पर आयात से प्रभावित फसलों के लिए मुआवज़ा तंत्र विकसित करना होगा। किसानों के बीज अधिकारों की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी लिखित वादा करना होगा। अमरीका-भारत व्यापार समझौता केवल आर्थिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि देश की कृषि और करोड़ों किसानों के भविष्य से जुड़ा सवाल है।

**पारदर्शिता की मांग**- आज विरोध, असंतोष और आशंका इस बात का संकेत हैं कि नीति और ज़मीनी हकीकत के बीच दूरी बढ़ रही है। यदि सरकार किसानों की आवाज़ नहीं सुनेगी, तो यह समझौता विकास का नहीं, बल्कि नए संकट का कारण बन सकता है। लेकिन यदि पारदर्शिता, संवाद और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सम्भवत: यह समझौता किसानों के लिए एक अवसर भी सिद्ध हो सकता है। बेहतर तो यही होगा कि सरकार जल्दबाजी न दिखाते हुए एक समिति का गठन कर इस पर व्यापक विचार-विमर्श कर ही आगे बढ़े।

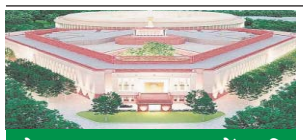

### लोकसभा/राज्यसभा में कृषि

(निमिष गंगराड़े)

# पीएम किसान : 30 लाख से अधिक किसानों का लंबित आधार-बैंक लिंकिंग मामला

**नई दिल्ली (कृषक जगत)।** केंद्र सरकार की प्रमुख किसान आय सहायता योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वर्ष 2019 में शुरू होने के बाद से अब तक 21 किस्तों के माध्यम से किसानों को रू. 4.09 लाख करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। हालांकि, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार तालिका के अनुसार देशभर में 30 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों का आधार से लिंक होना अभी भी लंबित है, जिसके कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह जानकारी कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक के पास कृषि योग्य भूमि होना तथा बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है।

**30.18 लाख किसानों की आधार लिंकिंग लंबित**

कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक विवरण के अनुसार 6 फरवरी 2026 तक देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 30,18,361 किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं।

राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 10,44,200 किसानों की आधार-बैंक लिंकिंग लंबित है। इसके बाद गुजरात (2,90,358), राजस्थान (2,13,779), मध्य प्रदेश (1,87,011) और महाराष्ट्र (1,72,349) का स्थान है। इसके अलावा बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी बड़ी संख्या में किसान इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार से बैंक खाता लिंक नहीं होने पर पीएम-किसान की किस्त जारी नहीं की जा सकती। जैसे ही किसान आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हैं, उनकी बकाया राशि तुरंत आधार से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

**आधार सीडिंग के लिए विशेष अभियान**

सरकार ने बताया कि किसानों के बैंक खाते समय-समय पर बदलने के कारण आधार सीडिंग की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। लाभार्थियों तक योजना का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सहयोग से विशेष अभियान चला रहा है।

## कृषक जगत डायरी 2026 विशिष्टजनों के हाथों में

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में गतदिनों आयोजित दलहन सम्मेलन में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं छग के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्रीद्वय श्री रामनाथ ठाकुर एवं श्री भागीरथ चौधरी, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट एवं केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के निदेशक श्री सी. आर. मेहता को कृषक जगत डायरी भेंट करते हुए अतुल सक्सेना।

# प्रदेश में मत्स्य उत्पादन दोगुना करने सक्रियता से करें कार्य : डॉ. यादव

## मत्स्य विभाग की समीक्षा, संभाग स्तर पर बनेंगे मछली घर

**भोपाल (कृषक जगत)।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी किसानों और मछुआरों की आर्थिक समृद्धि के लिए संकल्प के साथ कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है, इसके साथ हमें मत्स्य उत्पादन में भी सक्रियता से कार्य कर आने वाले वर्षों में इसे दोगुना करने की दिशा में काम करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रदेश में मछली पालन के साथ ही एक्वाकल्चर के क्षेत्र में भी कार्य किया जाए। प्रदेश में ऐसा इको सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे मछुआरों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार कृषक कल्याण को समर्पित करते हुए यह वर्ष मना रही है। मध्यप्रदेश को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश का नंबर-1 राज्य बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करें। मछुआ सम्मेलन आयोजित कर मत्स्य पालन में बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। सीड प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में कार्य करें। प्रदेश में संचालित मत्स्य महासंघ के सुव्यवस्थित उपयोग के लिए भी कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि कम भू-जल स्तर वाले जिलों में फॉर्म पॉन्ड मॉडल के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए एक जिले को मॉडल के रूप में तैयार किया जाए, जिसमें मत्स्य उत्पादन के साथ ही सिंघाड़ा, कमल गट्टा, मखाना सहित अन्य एक्वाकल्चर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संभाग स्तर पर मछली घर तैयार करने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के विभागीय योजनाओं की प्रगति, किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष प्रोजेक्ट, केज कल्चर इंदिरा सागर जलाशय, टेक्नोलॉजी डिफ्यूशन सेंटर, रिजर्वायर कलस्टर आधारित मत्स्य पालन और समन्वित मछली घर एवं अनुसंधान केंद्र का बैठक में रिव्यू किया। इस अवसर पर मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पंवार, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री नीरज मंडलोई एवं अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

## लाड़ली बहनों के खाते में आये 1836 करोड़

**मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गत शनिवार खंडवा जिले के पंधाना से राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 1836 करोड़ रूपये की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। अब तक इस योजना के तहत 52,304 करोड़ रूपये की राशि बहनों के खाते में डाली जा चुकी है। कार्यक्रम में जल संशाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।**

# श्री मनीष सिंह आयुक्त जनसंपर्क, श्री भार्गव संचालक कृषि बने

## 11 आईएएस अफसर बदले

**मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सौजन्य भेंट करते हुए नवनियुक्त जनसंपर्क आयुक्त श्री मनीष सिंह।**

**भोपाल (कृषक जगत)।** प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों के तबादले कर प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। इस फेरबदल में कई अहम विभागों के प्रमुख बदले गए हैं। कृषि संचालक श्री अजय गुप्ता को हटाकर मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर का प्रबंध संचालक बनाया गया है। राज्यपाल के अपर सचिव रहे श्री उमाशंकर भार्गव को कृषि विभाग का संचालक नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। वहीं 2009 बैच के आईएएस अधिकारी श्री मनीष सिंह को जनसंपर्क विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। वे पूर्व में भी यह दायित्व निभा चुके हैं। उनके पास परिवहन विभाग और जेल विभाग पहले की तरह रहेंगे। साथ ही मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहेगा। अब तक जनसंपर्क विभाग संभाल रहे श्री दीपक कुमार सक्सेना को आबकारी आयुक्त, ग्वालियर नियुक्त किया गया है। वहीं श्री अभिजीत अग्रवाल को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल का प्रबंध संचालक बनाकर वापस बुलाया गया है।

**श्री उमाशंकर भार्गव, संचालक कृषि**

अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल को वन विभाग से हटाकर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी विभाग का दायित्व सौंपा गया है। उनके पास पहले से मौजूद एपीसी पद, पर्यावरण विभाग भी यथावत रहेगा, साथ ही उन्हें खाद्य सुरक्षा आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रमुख सचिव श्री संदीप यादव को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से हटाकर वन विभाग का प्रमुख बनाया गया है। उन्हें प्रवासी भारतीय विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

भिंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील दुबे को राज्यपाल का उप सचिव बनाया गया है।

# सहकारिता में नवाचार उपलब्धियों का प्रजेंटेशन तैयार करें : श्री सारंग

## प्रदेश के सहकारिता मंत्री सम्मेलन में लेंगे भाग

**भोपाल (कृषक जगत)।** सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग में किये गये नवाचार एवं उपलब्धियों से संबंधित प्रजेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा चाही गयी बिन्दुवार जानकारी तैयार की जाये। जानकारी पूर्णत: अद्यतन हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। श्री सारंग मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में 17 फरवरी को होने वाले प्रस्तावित सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में आयोजित की गयी थी।

श्री सारंग ने कहा कि प्रजेंटेशन में सहकारिता विभाग की विशेषताएँ एवं उपलब्धियों सहित सीपीपीपी मॉडल, चीता बीज और नवाचारों का भी समावेश किया जाये। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में किये गये सर्वोत्तम कार्यों की जानकारी भी दी जाये। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र में सर्कुलेरिटी एवं सस्टेनेबिलिटी का भी समावेश किया जाये। सहकारिता में सहकार अभियान के तहत दुग्ध, मत्स्य सहित अन्य सहकारी संस्थाओं तथा उनके सदस्यों के खातों की संख्या दर्शाई जाये। प्रचार-प्रसार की दृष्टि से किये गये प्रयासों को भी बतायें। प्रजेंटेशन को अद्यतन जानकारी के साथ आकर्षक बनाया जाये और कम्पाइल प्रजेंटेशन तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करें।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि पेक्स का बहुउद्देश्यीकरण, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजनाएँ एवं सहकारिता क्षेत्र को लाभ, वित्तीय सहायता आदि का समावेश किया जाये।

## निर्यात प्रोत्साहन के लिए संभाग-स्तरीय जागरूकता कार्यशालाओं का होगा आयोजन

**भोपाल।** प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को निर्यात संबंधी नियम-कायदों की जानकारी देने के लिए गत 13 फरवरी से प्रदेश के 7 संभागों में संभागीय स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन एवं जागरूकता कार्यशाला शुरू हो गई है। सचिव एमएसएमई श्री दिलीप कुमार ने बताया कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन के समन्वय से होने वाली इन कार्यशालाओं की श्रृंखला में पहली उज्जैन में दूसरी इंदौर में हो गई है। 27 फरवरी को भोपाल, 28 फरवरी को जबलपुर, 7 मार्च को ग्वालियर, 13 मार्च को रीवा एवं 14 मार्च 2026 को सागर में संभाग-स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन एवं जागरूकता कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक **विजय कुमार बोन्द्रिया** द्वारा 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल से प्रकाशित एवं कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, भोपाल (मध्य प्रदेश) से मुद्रित, **सम्पादक : सुनील गंगराड़े,** फोन : 0755-4248100, 2554864, फैक्स : 0755-2571449. E-mail-info@krishakjagat.org इस अंक का मूल्य रु. 12/- वार्षिक शुल्क रु. 600/-.भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रमांक 1832/57

कृषक जगत
संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्द्रिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराड़े

**अमृत जगत**

*मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है न कि दूसरों की कृपा से।*
*- लाला लाजपत राय*

# सिंचाई और कृषि का चोली-दामन का साथ

सिंचाई और कृषि का चोली-दामन का साथ है। सदियों से कृषि के प्रमुख आदानों में जल के महत्व को सभी जानते हैं। भारतीय कृषि कुछ दशक पूर्व तक पूरी तरह से मानसून की दासी ही तो थी। बढ़ती जनसंख्या खाद्यान्नों के लिये बढ़ती मांग के चलते प्रति इकाई अधिक उत्पादन की ओर सभी संबंधितों का ध्यान गया और महसूस किया गया कि उत्पादन बढ़ने के लिए सबसे जरूरी आदान जल है। मानसून के प्राप्त जल से खरीफ का पेट तो भर जाता है। परंतु रबी की फसलों के लिये केवल भूमि में संचित नमी पर्याप्त नहीं हो सकती है। जरूरत अविष्कारों की जननी है परिणामस्वरूप देश में जगह-जगह छोटे, मध्यम तथा बड़े बांधों का निर्माण किया गया ताकि सदियों पुराने बने तालाब, नकलूप तथा कुएं के अलावा अतिरिक्त जल भंडार तैयार हो सके जिनसे फसलों की प्यास बुझाने के अलावा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके। इन बांधों से कमांड क्षेत्रों का विस्तार हुआ नहरों का मकड़जाल बिछाया गया और प्यासे खेतों तक सिंचाई की पुख्ता व्यवस्था की गई। सिंचाई का शाब्दिक मतलब होता है। सींचना/गीला करना ना की लबालब भरना। सींचने की परिभाषा को पकड़कर उसका अंगीकरण आज की जरूरत बन गई है। आंकड़े बतलाते हैं धरा पर उपलब्ध जल का केवल 27 प्रतिशत ही उपयोगी है। समुद्र में भरा अथाह जल किसी काम का नहीं है अतः इस सीमित जल की बूंद-बूंद का उपयोग सावधानी से

किया जाये। उल्लेखनीय है कि बांधों की क्षमता कुल बोये जाने वाले क्षेत्र का 20-22 प्रतिशत ही पूरा कर सकता है एक हेक्टर असिंचित भूमि को सिंचित बनाने के लिए शासन को आज एक-दो दशक पहले एक लाख तक का खर्च आता था जो वर्तमान में दोगुना हो गया है इस कारण इस दिशा में प्रगति तो है परंतु अभी अपेक्षायें आगे भी हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि एक बार सिंचाई के विस्तार के बाद फसल सघनता 100 प्रतिशत से बढ़कर 200 और आंशिक क्षेत्रों में 300 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। यदि समझा जाये तो जहां-जहां भी सिंचाई के कदम आये वहां-वहां उल्लेखनीय प्रगति हुई ग्रामीण अंचलों में जहां साईकिल नहीं मिलती थी आज चार पहिये वाहनों, ट्रैक्टरों के ढेर लग चुके हैं। यदि आकलन किया जाये जितना खर्च बांधों के निर्माण में किया गया उसका कई गुना धन कमाया जा चुका है। वर्तमान में क्षेत्र में धान का भी विस्तार हो रहा है गेहूं की उत्पादकता दो गुना बढ़ गई जो अपने आप में एक 'रिकॉर्ड' है। सिंचाई के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। जरूरत केवल इतनी ही है कि सिंचाई कब की जाये कितनी की जाये कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा प्रत्येक फसल की क्रांतिक अवस्था आज जगजाहिर है जिस पर सिंचाई की जाना जरूरी होता है जिसका असर उत्पादन पर फौरन पड़ता है। उसका पालन किया जाये नहरों में बहता जल, बांधों में भरी जल सम्पदा केवल आज कृषकों की है, कृषकों के लिये ही है तो फिर उसका दुरुपयोग क्यों अधिक पानी मिट्टी के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है क्योंकि पानी के साथ उर्वरकों का भी उपयोग असंतुलित मात्रा में किया जाता है क्योंकि जल जीवन है तो उसका उपयोग भी जीने के उद्देश्य से ही किया जाये तो बेहतर होगा। सिंचाई और कृषि का यह चोली-दामन का साथ सदियों तक बना रहे इसी भावना से उसका सद्उपयोग प्रगति के मार्ग प्रशस्त करेगा।

# वैश्विक समझौतों की बिसात पर छोटे पशुपालक

● निलेश देसाई

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार 'हल और हंसिया' नहीं, बल्कि वह खूंटा है जिससे बंधी गाय, भैंस या बकरी किसी भी आपदा में किसान की रसोई जलने की गारंटी देती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और मांस उत्पादन में भी अग्रणी है, लेकिन आज, फरवरी 2026 के इस मोड़ पर, भारत का पशुपालन क्षेत्र एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ 'बजट 2026' की तकनीक-आधारित आधुनिकता की चमक है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और 'यूरोपीय संघ' के साथ हुए व्यापार समझौतों का वह चक्रव्यूह है।

**वैश्विक समझौतों के 'बारीक अक्षर'**

फरवरी 2026 में हुए 'भारत-अमेरिका व्यापार अनुबंध' को सरकार ने 'ऐतिहासिक' करार दिया है। वाणिज्य मंत्रालय का तर्क है कि इससे भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए व्यापार के नए रास्ते खुले हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में 'सुरक्षा' एक सापेक्ष शब्द है। अमेरिका लंबे समय से भारत के 'पोल्ट्री' (मुर्गी पालन) और 'डेयरी' बाजार पर नजर गड़ाए हुए है।

सबसे बड़ा खतरा 'चिकन लेग्स' की 'डंपिंग' का है। अमेरिका में 'ब्रेस्ट मीट' की मांग अधिक है और वहां 'चिकन लेग्स' को उप-उत्पाद मानकर बहुत कम कीमत पर बेचा जाता है। यदि व्यापारिक दबाव के तहत भारत इन पर 'आयात शुल्क' घटाता है, तो भारत के वे लाखों छोटे पोल्ट्री किसान जो 100-200 मुर्गियों से अपनी आजीविका चलाते हैं, रातों-रात बाजार से बाहर हो जाएंगे। वे अमेरिकी कंपनियों की उस कीमत का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे जिसे वहां की सरकार भारी सब्सिडी देती है। यही डर डेयरी क्षेत्र में भी है। 'यूरोपीय संघ' के साथ चल रही बातचीत में अक्सर 'प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों' पर रियायत मांगी जाती है। यदि विदेशी मक्खन, पनीर और मिल्क पाउडर बिना किसी रोक-टोक के भारतीय बाजारों में आए, तो हमारी सहकारी समितियों का ढांचा चरमरा सकता है, जो

करोड़ों छोटे दुग्ध उत्पादकों को 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (एमएसपी) जैसा भरोसा देता है।

इस वैश्विक दबाव के बीच, वित्तमंत्री ने 'बजट 2026' में पशुपालन क्षेत्र के लिए 6,153 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। सरकार का तर्क है कि तकनीक के जरिए हम पशुपालक की उत्पादकता बढ़ाएंगे, ताकि वह वैश्विक बाजार में मुकाबला कर सके, लेकिन यहाँ एक गहरा अंतर्विरोध है।

**घाना और मेक्सिको: इतिहास की अनसुनी चेतावनी**

ऐसे में उन देशों की याद करना जरूरी है जिन्होंने व्यापार समझौतों के नाम पर अपने पशुपालकों की बलि दे दी। घाना कभी पोल्ट्री में आत्मनिर्भर था, लेकिन 2000 के दशक में यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौतों ने वहां के बाजारों को 'फ्रोजन चिकन' से भर दिया। परिणाम घाना का अपना पोल्ट्री उद्योग 90त्न तक नष्ट हो गया। आज वहां के बाजारों में स्थानीय मांस गायब है।

मेक्सिको ने 1994 में अमेरिका के साथ 'मुक्त व्यापार समझौता' किया। वहां के छोटे सुअर और बकरी पालकों को लगा कि उन्हें अमेरिकी बाजार मिलेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। अमेरिकी कॉर्पोरेट फार्मों ने अपनी सब्सिडी की दम पर मेक्सिको के स्थानीय बाजार पर कब्जा कर लिया। लाखों छोटे किसान विस्थापित हुए और वे शहरों में मजदूर बनने को मजबूर हो गए। क्या भारत भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है?

**'बीज विधेयक 2025' और चारे की राजनीति**

पशुपालन का सीधा संबंध चारे से है। प्रस्तावित 'बीज विधेयक 2025' बीजों पर कॉर्पोरेट एकाधिकार को बढ़ावा दे सकता है। पशुपालक के लिए चारा (मक्का, सोयाबीन, ज्वार) मुख्य इनपुट है। यदि बीजों की लागत बढ़ती है, तो पशुओं को पालना महंगा होगा। यदि हम अपनी स्वदेशी किस्मों की बजाय कंपनियों के 'संकर' बीजों पर निर्भर हो गए, तो पशुपालक की आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी।

**भारत सरीखे कृषि प्रधान देश में वैश्विक व्यापार समझौतों का सीधा असर कृषि और किसानों पर होता है। वैसे भी हमारे यहां कृषि और पशुपालन, प्राथमिक रूप से व्यापार की बजाए पेट भरने की तकनीक मानी जाती है और ऐसे में इनके साथ की जाने वाली मामूली सी छेड़छाड़ सीधे खाद्य-सुरक्षा को संकट में डाल सकती हैं। ऐसे में हाल के वैश्विक व्यापार समझौतों का हमारे पशुपालकों पर क्या असर होगा?**

बीज और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं; एक की आजादी छिनी, तो दूसरा खुद-ब-खुद गुलाम हो जाएगा।

**क्या बजट व्यापार समझौतों का मुकाबला कर पाएगा?**

'बजट 2026' में की गई 27 प्रतिशत की वृद्धि सराहनीय है, लेकिन क्या यह अंतरराष्ट्रीय समझौतों के असर रोकने के लिए काफी है?

**बाजार बनाम सब्सिडी:** यदि समझौतों के तहत आयात शुल्क 0त्न कर दिया जाता है, तो बजट की मामूली सब्सिडी किसान का घर नहीं बचा पाएगी।

**कॉर्पोरेट कब्जा:** बजट का बड़ा हिस्सा तकनीक और स्टार्टअप्स पर केंद्रित है। डर यह है कि यह पैसा छोटे पालकों तक पहुँचने के बजाय उन 'एग्री-टेक' कंपनियों की जेब में जाएगा जो पशुपालन को केवल एक डेटा और मुनाफे की मशीन मानती हैं।

**समाधान की राह: संप्रभुता का संरक्षण**

भारत को यदि अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाना है, तो उसे 'विकास' की परिभाषा बदलनी होगी। हमें केवल 'निर्यात' के आंकड़ों को नहीं, बल्कि 'अंतिम छोर के पशुपालक' की आय को पैमाना बनाना होगा।

**सुरक्षात्मक टैरिफ:** सरकार को किसी भी दबाव में आकर डेयरी और पोल्ट्री पर आयात शुल्क कम नहीं करना चाहिए। 'रेड लाइन' केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर दिखनी चाहिए।

**डिजिटल सुरक्षा, न कि निगरानी:** तकनीक का उपयोग किसान को सुविधा देने के लिए हो, न कि उसे बाजार से बाहर करने के लिए।

**स्वदेशी नस्लों का संवर्धन :** हमारी बकरियां और मुर्गियां कम खर्च में बेहतर प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। हमें विदेशी नस्लों के बजाय अपनी स्थानीय नस्लों के सुधार पर निवेश करना चाहिए।

**सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण :** 'अमूल' जैसे मॉडलों को पोल्ट्री और बकरी पालन में भी लागू करना होगा, ताकि कॉर्पोरेट कंपनियां सीधे किसान का शोषण न कर सकें।

भारत के सामने आज जो परिदृश्य है, वह केवल अर्थव्यवस्था का नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक सुरक्षा और संस्कृति का है। पशुपालन करोड़ों भूमिहीन दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का एकमात्र सहारा है। यदि व्यापारिक समझौतों की चमक में हमने अपने इस 'मूक,' लेकिन 'मजबूत' आधार को खो दिया, तो हम अपनी खाद्य सुरक्षा को कॉर्पोरेट तिजोरियों में गिरवी रख देंगे। समय की मांग है कि बजट की राशि का उपयोग छोटे पशुपालकों के लिए 'कवच' बनाने में किया जाए, न कि कॉर्पोरेट के लिए 'कालीन' बिछाने में। जिस देश का पशुपालक और बीज किसी कंपनी की शर्तों पर निर्भर हो जाता है, उस देश की थाली कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती।

**(सप्रेस)**

# फसलों की गहाई एवं सुरक्षा के उपाय

कृषि में मशीनों के उपयोग से जहां पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई है। वहीं मशीन संबंधित दुर्घटनाओं की संख्याओं में भी बढ़ोत्तरी हुई है इन दुर्घटनाओं से होने वाले जान माल का नुकसान ना सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए बल्कि समूचे समाज और राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मशीनीकरण के शुरुआती दौर में थ्रेशर से हुए हादसों की संख्या बहुत अधिक थी, जिसमें व्यक्तियों की उंगलियों और हाथ का शारीरिक नुकसान हुआ है इन कारणों को मद्देनजर रखते हुए थ्रेसर से सुरक्षा के लिए शोध किया गया है, तथा सुरक्षित परनाला (हापर) के साथ–साथ कई सुरक्षित उपायों की खोज की गई है, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या काफी कम हुई है। थ्रेसर से होने वाले हादसे गेहूं, धान सोयाबीन आदि फसलों की कटाई व गहाई के दौरान अधिकतर सामने आते हैं। जिनका मुख्य कारण कार्य करते समय नशा और शराब का सेवन करना है, कई घंटे लगातार काम करते रहना, थकावट, थ्रेशर में सुरक्षा प्रणाली की कमी, मशीन के बारे में अधूरी जानकारी, ढीले कपड़े, या दुपट्टा या लंबे बालों का मशीन से उलझना आदि अन्य कारण है। इन दुर्घटनाओं को मशीन में सुरक्षित प्रणालियों का उपयोग करके तथा जरुरी सावधानियों को ध्यान में रखकर घटाया जा सकता है।

### थ्रेशर के लिए सुरक्षित प्रणालियां

● बीआईएस के अनुसार थ्रेशर के हापर की लंबाई कम से कम 3 फुट तथा ऊपर के कवर की लंबाई 1.5 फुट होनी चाहिए इसके उपयोग से हाथ थ्रेसर के ड्रम के अंदर जाने से सुरक्षित रहता है।

● **फसल वापस खींचने वाला यंत्र–** यह सुरक्षा यंत्र थ्रेशरों में लगाया जाता है जिसमें फसल को अंदर खीचने के लिए फिडिंग रोलर लगे होते है। इसमें एक रिवर्स गियर सिस्टम होता है, जिसमें हापर के पास एक गियर लीवर लगा होता है। इस गियर लीवर के लगाने से फीडिंग रोलर विपरीत दिशा में घूमने लगते है। यदि किसी व्यक्ति का हाथ फीडिंग रोलर में फस जाता है। तुरंत यह गियर लीवर दबाने से व्यक्ति का हाथ मशीन के अंदर जाने के बजाय, मशीन से बाहर आने लगता है।

● गतिमान पुर्जो पर कवर– चलते हुए पूर्जे जैसे बेल्ट, पुल्ली, फ्लाई व्हील, चेन, शाफ्ट, गियर आदि के ऊपर कवर लगा कर थ्रेशर से संबंधित हादसों को कम किया जा सकता है।

● **फसल थ्रेशिंग ड्रम तक पहुंचाने वाला बेल्ट कन्वेयर सिस्टम–** बड़े हडम्बा थ्रेसर में बेल्ट चेन वाली एक प्रणाली लगा कर फसल के गट्ठे को थ्रेशर के ड्रम तक पहुंचाया जा सकता है, यह प्रणाली फसल के गट्ठे को आदमी की कोहनी के बराबर ऊंचाई से उठाकर थ्रेशर के ड्रम के अंदर पहुंचाती है। इसके उपयोग से जहां थ्रेशर से होने वाले हादसों को कम किया जा सकता है साथ ही साथ काम करने वाले व्यक्ति बड़े आराम से लम्बे समय तक काम कर सकते है।

### थ्रेसर का उपयोग करते समय जरुरी सुरक्षा व सावधानियां

● थ्रेशर दुर्घटनाओं से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित परनाला (हापर) तथा हडम्बा थ्रेशर खरीदने वाले किसान भाई फसल वापिस खीचने वाला यंत्र जरुर लगाये।

● थ्रेशर के आसपास की जगह खुली तथा बिना किसी रुकावट की हो।

● बिजली की मोटर को बंद करने वाला बटन काम करने वाले व्यक्ति के पास लगा होना चाहिए, जिससे आपातकाल में मोटर जल्दी बंद कर सके।

● थ्रेशर में फसल लगाने वाला व्यक्ति अनुभवी तथा जानकार होना चाहिए।

● थ्रेशर पर काम करते समय ढीले कपड़े खासतौर पर धोती, दुपट्टा, खुली बाह वाली कमीज तथा घड़ी या कड़ा ना पहने।

● नशा कर या शराब का सेवन करके थ्रेशर पर काम न करें।

● थ्रेशर रात के समय खासतौर पर बिना उचित रोशनी के नहीं चलाये।

● पीटीओ शाफ्ट के ऊपर से या आसपास से ना गुजरे।

● धूल तथा भूसा से बचने के लिए नाक पर कपड़े सा मास्क तथा आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का प्रयोग करें।

● किसी भी आदमी को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करायें, थकावट व अनिद्रा से हादसे की संभावना बढ़ जाती है।

● काम करते समय बात ना करे किसी और तरफ ध्यान न बाटे तथा थ्रेशर चलते समय किसी भी पुर्जे को खोलने या कसने की कोशिश न करें।

# कटाई - गहाई बड़े ध्यान से

**फसल उत्पादन की प्रक्रिया में फसल कटाई–गहाई और भंडारण व्यवस्था की अहम भूमिका होती है जो कि बिना किसी लागत के कृषक का लाभ बढ़ा सकती है, इसके विपरीत थोड़ी सी भी लापरवाही काफी नुकसान पहुंचा सकती है। एक अनुमान के अनुसार फसल के काटने से लेकर उसके भंडार में पहुंचने के दौरान लगभग 5–10 प्रतिशत उपज का नुकसान और भंडारण के दौरान भी लगभग इतना ही नुकसान हो जाता है। अतः यह अति आवश्यक है कि किसान भाई कुछ आसान तथ्यों को ध्यान में रखकर खेतों में कटाई से लेकर भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपनी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं।**

### फसल कब काटें

● फसल की औसत अवधि को ध्यान में रखते हुए फसल का अच्छी तरह निरीक्षण करें।

● दलहनी तथा तिलहनी फसलों में कम से कम नीचे से 25 प्रतिशत पत्तियां झड़ गई हों तथा अनाज फसलें जैसे गेहूं में पत्तियां सूख गई हों।

● तने का रंग पीला हो गया हो।

● फली, कैपसूल, बाली का रंग पीला, सुनहरा हो गया हो।

● फसल खेत में पूरी तरह सूखने से पहले काट कर खलिहान में सूखने की व्यवस्था करनी चाहिए।

● फसल काटने में देरी करने से फली या बाली झड़ जाने की संभावना होती है और दाने खेत में गिर जाने से उत्पादन में भी नुकसान होता है।

● फसल कटाई के लिए अनुभवी व्यक्तियों को कार्य में लगाएं।

### कटाई

● पौध कार्यकीय परिपक्वता ( फिजियोलोजिकल मैच्योरिटी) पर जब 75 प्रतिशत फलियों या बालियां पीली पड़ जाये तब फसल को काटना चाहिये, ताकि फलियां चटकने से बच सकें।

● कटाई का कार्य सुबह के समय करें क्योंकि नमी होने के कारण फलियां, बालियां खेत में नहीं बिखरेंगी।

● समय पर कटाई होने से उच्च गुणवत्ता तथा बाजार में उपभोक्ता द्वारा पसंद की जाने वाली गुणवत्ता की उपज प्राप्त होती है, इससे बाजार में उत्पाद का भाव अच्छा मिलता है।

● कटाई करने के बाद पौधों को खेत से उठा कर खुले स्थान पर फिर खेत में ही फैला कर सूखने के लिए रखना चाहिए। सरसों तथा अन्य आसानी से झड़ने वाली फसलों को कटाई के तुरंत बाद खलिहान में स्थानांतरित करें।

● रात के समय खलिहान में फसल को घास–फूस या बड़े तिरपाल से ढ़ंक दें, ताकि रात में ओस गिरने से फसल गीली न हो।

● प्रतिकूल मौसम में कटाई न करें।

● कटाई तथा ढुलाई करते समय विशेष ध्यान रखें कि फसल के साथ किसी प्रकार का अपमिश्रण न होने पाये (जैसे मिट्टी के ढेले, पत्थर अन्य पौधे आदि जिनका बाद में अलग करने में कठिनाई हों और फसल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हों।)

● कटाई के लिए उपयुक्त विधि का प्रयोग करें। कांटेदार फसल जैसे कुसुम की कटाई हाथ में दस्ताने पहनकर या उसे कपड़े से लपेटकर या दो शाखा वाली लकड़ी में पौधे का फंसाकर दराते से करना चाहिए।

● यदि कटाई हार्वेस्टर के द्वारा करनी हो तो इसके लिए कृषक भाई फसल को खेत में पूर्ण रुप से परिपक्व होने पर काटें। खेत में मौजूद खरपतवार के पौधों तथा अन्य फसल के पौधों को कटाई से पहले निकाल दें ताकि किसी प्रकार के अपमिश्रण से बचा जा सके।

● कटाई चालू करने से पहले यह अवश्य जांच लें कि हार्वेस्टर पूर्ण रुप से साफ है तथा ठीक ढंग से काम कर रहा है।

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

# गेंदे की खेती : कम लागत में दोगुना मुनाफा

● आरती कुशवाहा (कृषि स्नातक)
● संदीप कुमार शर्मा (कृषि मौसम वैज्ञानिक)
● डॉ. संजय सिंह (वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी)
जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, रीवा

गेंदा भारत में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उगाए जाने वाले पुष्पों में से एक है। गेंदा अपनी आकर्षक रंगत, सुगंध, लंबी ताजगी और बहुउपयोगिता के कारण सामाजिक, धार्मिक, औषधीय और कृषि दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

**वर्गीकरण** (CLASSIFICATION)

**परिवार (Family name):** एस्टरेसी (Asteraceae) (जिसे कम्पोजिटे परिवार भी कहते हैं)

**वैज्ञानिक नाम (Scientific names):** Tagetes erecta तथा Tagetes patula

**धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व**

भारत में गेंदा का फूल पूजा-पाठ, त्योहारों, विवाह और अन्य मांगलिक अवसरों में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इसकी चमकीली पीली और नारंगी रंगत शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर सजावट, माला निर्माण और धार्मिक आयोजनों में इसका व्यापक प्रयोग होता है।

**सजावटी महत्व**

गेंदा बागवानी और सजावट के लिए अत्यंत लोकप्रिय है। इसे घरों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और समारोहों की सजावट में उपयोग किया जाता है। इसकी आसान खेती और लंबे समय तक खिले रहने की क्षमता इसे सजावटी पौधों में विशेष स्थान देती है।

**औषधीय महत्व**

गेंदा में एंटीसेप्टिक और सूजनरोधी गुण पाए जाते हैं। पारंपरिक चिकित्सा में इसका उपयोग त्वचा संबंधी समस्याओं, घाव भरने और संक्रमण से बचाव के लिए किया जाता है।

**कृषि में महत्व**

गेंदा का पौधा कीट नियंत्रण में सहायक माना जाता है। इसे सहफसली (trap crop) के रूप में उगाया जाता है क्योंकि यह कुछ हानिकारक कीटों को आकर्षित कर मुख्य फसल की रक्षा करता है। इससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो सकती है।

**सामान्य नाम (Common names):** अफ्रीकन गेंदा एवं फ्रेंच गेंदा ।

**जलवायु आवश्यकताएँ**

**तापमान**

धूप वाली जगहों में अच्छी वृद्धि करता है तथा गर्म एवं आर्द्र दोनों परिस्थितियों में बढ़ सकता है। अत्यधिक ठंड एवं पाला इसे नुकसान पहुँचाता है। बीज अंकुरण के लिए आदर्श तापमान 18-30 डिग्री सेंटीग्रेट तथा उत्तम वृद्धि के लिए 15-29 डिग्री सेंटीग्रेट है। 26 डिग्री सेंटीग्रेट से अधिक तापमान फूल बनने को प्रभावित कर सकता है।

**वर्षा**

गेंदा उत्पादन के लिए उपयुक्त वार्षिक वर्षा की मात्रा स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है।

**मृदा आवश्यकताएँ**

गेंदा विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, परंतु हल्की, कार्बनिक पदार्थ से युक्त एवं जल निकास वाली मिट्टी उपयुक्त है। गहरी, उपजाऊ, भुरभुरी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो तथा पीएच मान 7-7.5 (तटस्थ) हो, सर्वोत्तम है। अत्यधिक उर्वर मिट्टी में पत्तियाँ अधिक और फूल कम लगते हैं।

**दूरी**

**टेगेटेस इरेक्टा ( अफ्रीकन गेंदा)**

40 X 40 सेमी
40 X 30 सेमी
45 X 30 सेमी
60 X 45 सेमी

**टेगेटेस पाटुला ( फ्रेंच गेंदा)**

20 X 20 सेमी
20 X 10 सेमी
30 X 30 सेमी
30 X 20 सेमी

**कृषि क्रियाएँ**

**प्रवर्धन**

गेंदा का प्रवर्धन बीज एवं कलम दोनों से किया जाता है। बीजों को खेत में सीधे या ट्रे में बोया जा सकता है। बीजों को 1 सेमी गहराई पर तथा 2 सेमी दूरी पर बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। ठंड की संभावना होने पर बीज ट्रे में बोए जाते हैं। बीज 4-7 दिनों में अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण के बाद पौधों की छंटाई कर उचित दूरी बनाए रखें। पौधे 8-10 सप्ताह में फूल देना शुरू कर देते हैं। कलम विधि शुद्धता बनाए रखने के लिए उपयोग की जाती है। 10-15 सेमी लंबी कलम लेकर रूटिंग पाउडर से उपचारित कर हल्की रेतीली मिट्टी में लगाई जाती है।

**भूमि तैयारी**

छोटे बगीचों में हाथ के औजारों से तथा बड़े खेतों में मशीनों द्वारा भूमि तैयार की जाती है।

भूमि को भली-भांति जोतकर खरपतवार हटाएँ। यदि भूमि कठोर हो तो ट्रैक्टर से जुताई करें। बाद में हल्की जुताई कर मेड़ एवं नालियाँ बनाएँ।

**रोपण**

पौधों की दूरी 45X35 सेमी रखी जाती है।

**फ्रेंच (बौना) गेंदा** - 20X20 सेमी

**अफ्रीकन गेंदा** - 40X30 सेमी

रोपाई से पहले मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएँ। रोपाई के 30 दिन बाद शीर्ष भाग की छंटाई (पिंचिंग) करें ताकि शाखाएँ अधिक निकलें।

**उर्वरीकरण**

गेंदा हल्की जैविक खादयुक्त मिट्टी में अच्छा उत्पादन देता है। अधिक नाइट्रोजन से पौधा अधिक बढ़ता है पर फूल कम आते हैं।

**मुख्य पोषक तत्व** - नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश।

संतुलित उर्वरक प्रत्येक 6 सप्ताह में दें।

**सामान्य सिफारिश** NPK (200:100:100) किग्रा/हेक्टेयर या मिट्टी परीक्षण के अनुसार।

**खाद एवं उर्वरक**

**भूमि तैयारी के समय**: 100 किग्रा N + 100 किग्रा P + 100 किग्रा K प्रति हेक्टेयर मिलाएँ।

शेष 100 किग्रा नाइट्रोजन को 2 भागों में दें
रोपाई के 30 दिन बाद
रोपाई के 40 दिन बाद

**सिंचाई**

सिंचाई की आवृत्ति मौसम पर निर्भर करती है।

सामान्यतः 4-5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें।

**पिंचिंग**

प्रारंभिक अवस्था में शीर्ष भाग हटाया जाता है जिससे अधिक शाखाएँ और अधिक फूल प्राप्त होते हैं।

रोपाई के 40 दिन बाद पिंचिंग करने से फूलों की संख्या बढ़ती है।

**सहारा देना**

लंबे पौधों को सहारा देना आवश्यक है।

बाँस की लकड़ियों से सहारा दिया जाता है।

**खरपतवार नियंत्रण**

खरपतवार नियंत्रण का उचित समय भूमि तैयारी के दौरान होता है। खरपतवारों को हटाना आवश्यक है ताकि गेंदा पौधों और खरपतवारों के बीच पोषक तत्व एवं जल के लिए प्रतिस्पर्धा न हो। खरपतवारों को हाथ से भी निकाला जा सकता है। पूर्व-अंकुरण (Pre-emergence) शाकनाशी का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु निर्देशों का पालन आवश्यक है। प्रभावी नियंत्रण के लिए पंजीकृत रसायनों का उपयोग करें।

गेंदा पौधों के बीच मल्च (mulch) की परत बिछाने से खरपतवार कम होते हैं तथा मिट्टी की नमी संरक्षित रहती है, विशेषकर जब पौधे छोटे हों।

**कटाई**

फूल पूर्ण आकार आने पर तोड़ें।

सुबह या शाम के ठंडे समय में तुड़ाई करें।

तुड़ाई से पहले हल्की सिंचाई करें।

रात भर रखने पर फूलों को गीली बोरी से ढकें।

**उपज**

**अफ्रीकन गेंदा**: 11-18 टन/हेक्टेयर
**फ्रेंचगेंदा**: 8-12टन/हेक्टेयर

**कीट एवं रोग नियंत्रण कीट**

**लाल मकड़ी**: फूल आने के समय पौधों पर यह कीट दिखाई देता है जिससे पत्तियों पर धूल जैसा रूप दिखाई देता है।

**नियंत्रण उपाय**: पंजीकृत कीटनाशकों का प्रयोग करें।

**रोयेंदार सुंडी**: यह कीट गेंदा की पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है।

**रोग**

**गेंदा में मुख्य रोग** : डैंपिंग ऑफ, पत्ती धब्बा एवं झुलसा, तथा चूर्णिल आसिता (Powdery mildew) हैं।

**डैंपिंग ऑफ**:

नवीन पौधों में भूरे मृत धब्बे दिखाई देते हैं। यह जड़ गर्दन को प्रभावित कर पौधों को गिरा देता है। अंकुरण पूर्व एवं अंकुरण पश्चात मृत्यु हो सकती है।

**नियंत्रण उपाय**: नर्सरी में उचित जल निकास एवं वायु संचार की व्यवस्था करें।

**पत्ती धब्बा एवं झुलसा**: निचली पत्तियों पर छोटे भूरे गोल धब्बे बनते हैं जो बाद में बड़े होकर पत्तियों के झड़ने एवं पौधे की मृत्यु का कारण बनते हैं।

**नियंत्रण उपाय**: रोग के लक्षण दिखते ही पंजीकृत फफूंदनाशी का छिड़काव करें।

**चूर्णिल आसिता**: पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसे धब्बे बनते हैं जो बाद में पूरे पौधे को ढक लेते हैं।

**नियंत्रण उपाय**: पंजीकृत फफूंदनाशी का छिड़काव करें।

# संतुलित पशु आहार एवं इसकी उपयोगिता

● डॉ. अशोक कुमार पाटिल
● डॉ. लक्ष्मी चौहान
पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, महू
ashokdrpatil@gmail.com

पशु को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 24 घंटे में जितना चारा व दाना दिया जाता है, वह मात्रा राशन (आहार) कहलाती है। पशु को उसके शरीर भार के अनुसार, उसके जीवित रहने के लिए जीवन निर्वाह आहार, वृद्धि, उत्पादन व कार्य के लिए वर्धक आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार उस भोजन सामग्री को कहते हैं जो किसी विशेष पशु की 24 घंटे की निर्धारित पौषाणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संतुलित राशन में कार्बन, वसा और प्रोटीन के आपसी विशेष अनुपात के लिए कहा गया है। संतुलित आहार चारे व दाने का ऐसा मिश्रण होता हैं जिसमें पशु को स्वस्थ रखने, वृद्धि, उत्पादन या कार्य करने के लिये विभिन्न पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण एवं विटामिन आदि एक निश्चित मात्रा एवं निश्चित अनुपात में उपलब्ध होते हैं। संतुलित आहार में निम्न लिखित विशेष लक्षण होना चाहिये।

● आहार स्वादिष्ट एवं सुपाच्य हो।

● आहार स्वच्छ, पौष्टिक एवं सस्ता हो। यह विषैला, सड़ा–गला, दुर्गंध युक्त व अखाद्य पदार्थो से मुक्त हो।

● आहार आसानी से उपलब्ध, स्थानीय आहार अवयवों के उपयोग से बनाया जाना चाहिए ताकि सस्ता भी हो।

● चारा भली–भांति तैयार किया जाये। जिससे वह आसानी से पचने व रूचिकर बन सके। सख्त दाने जैसे–जौ, मक्का इत्यादि को चक्की से दलिया के रूप में दलवा लें।

● चारे व दाने का प्रकार अचानक बदलना नहीं चाहिये। चारे में धीरे–धीरे बदलाव लाना चाहिए, ताकि पशु की भोजन प्रणाली पर कुप्रभाव न पड़े।

● गाय एवं भैंसों में शुष्क पदार्थ की खपत प्रतिदिन 2.5 से 3.0 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के अनुसार होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 400 किलोग्राम वजन की गाय एवं भैंस को रोजाना 10–12 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। इस शुष्क पदार्थ को हम चारे और दाने में विभाजित करें तो शुष्क पदार्थ का लगभग एक तिहाई हिस्सा दाने के रूप में खिलायें।

● पशुओं में आहार की मात्रा उसकी उत्पादकता तथा प्रजनन की अवस्था पर निर्भर करती है। पशु को कुल आहार का 2/3 भाग

मोटे चारे से तथा 1/3 भाग दाने के मिश्रण द्वारा मिलायें। मोटे चारे में दलहनी तथा गैर दलहनी चारे का मिश्रण दिया जा सकता है। दलहनी चारे की मात्रा आहार में बढ़ने से काफी हद तक दाने की मात्रा को कम किया जा सकता है।

● खाने में सूखा चारा, हरा चारा, और पशु आहार को शामिल करें ताकि सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मिल सके। हरा चारे की पाचनशीलता सूखे चारे से अच्छी होती है एवं पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं। हरा चारा दूध का उत्पादन बढ़ाता है। इसमें सूडान घास, बाजरा, ज्वार, मकचरी, जई और बरसीम आदि शामिल हैं। पशुपालकों को चाहिए कि वो हरे चारे में दलिया या दलहनी दोनों तरह के चारे शामिल करें। इससे पशुओं में प्रोटीन की कमी बड़ी आसानी से पूरी की जा सकती है।

● यदि पशु आहार में हरा चारा शामिल है तो पौष्टिक मिश्रण में 10–12 प्रतिशत पाचक प्रोटीन हो। इसके विपरीत यदि हरा चारा नहीं है तो दाने में इसकी मात्रा कम से कम 18 प्रतिशत हो।

● पशुओं को प्रति 100 कि.ग्रा. शरीर भार पर 8–10 ग्राम खाने का नमक प्रतिदिन दें। इसके अतिरिक्त 2 प्रतिशत खनिज मिश्रण आहार में मिला कर दें।

● चारा खिलाने की नांद पूर्णतः स्वच्छ हो। उसमें नया चारा व दाना डालने से पूर्व बची हुई जूठन को बाहर निकाल दें।

## पशुओं के आहार में संतुलित दाना कितना खिलायें

वैसे तो पशु के आहार की मात्रा का निर्धारण उसके शरीर की आवश्यकता व कार्य के अनुरूप तथा उपलब्ध भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के आधार पर गणना करके किया जाता है लेकिन पशुपालकों को गणना कार्य की कठिनाई से बचाने के लिए थम्ब रुल को अपनाना अधिक सुविधा जनक है। इसके अनुसार हम मोटे तौर पर व्यस्क दुधारू पशु के आहार को निम्न वर्गों में बांट सकते हैं–

**हमारे प्राचीन काल से एक कहावत चली आ रही है की जैसा खाए अन्न वैसा होय तन ओर मन, अर्थात हमारे शरीर की वृद्धि व बनावट में खान पान का विशेष महत्त्व है। यही सिद्धांत पशुओ पर भी लागू होता है परन्तु हम जानते है की पशुओं का जीवन अधिकतर वनस्पति जगत पर ही निर्भर करता हैं। ओर हम यह भी जानते है की वनस्पतियों से प्राप्त भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होती है जिसके कारण पशुओ की शारीरिक वृद्धि तथा उत्पादन घटता है, इसलिए पशुओं को उनकी अवश्यकताओ की पूर्ति करते हुए खिलाना एक महत्वपूर्ण कला हैं। जो कि पशुपालकों के प्रयोगात्मक अनुभवनों के साथ–साथ विकसित होती आई है। वैज्ञानिक ढंग से पशुओं को खिलाने का तरीका बहुत समय से चला आ रहा है। पशु का आहार ऐसे पौष्टिक तत्वों से बना होना चाहिए जिससे उसकी अवश्यकतानुसार सभी पौष्टिक तत्व मिल सकें। चूंकि यह सभी तत्व उसे एक ही चारे में नहीं मिल सकते है। अतः पशु को विभिन्न प्रकार के आहारों पर निर्भर रहना पड़ता है।**

● **जीवन निर्वाह के लिए** – यह आहार की वह मात्रा है जो पशु को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिया जाता है। इसे पशु अपने शरीर के तापमान को उचित सीमा में बनाए रखने, शरीर की आवश्यक क्रियायें जैसे पाचन क्रिया, रक्त परिवाहन, श्वसन, उत्सर्जन, चयापचय आदि के लिए काम में लाता है। इससे उसके शरीर का वजन भी एक सीमा में स्थिर बना रहता है। चाहे पशु किसी भी अवस्था में हो उसे यह आहार की उचित मात्रा देना ही पड़ता है इसके आभाव में पशु कमजोर होने लगता है जिसका असर उसकी उत्पादकता तथा प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। गाय के लिए इसकी मात्रा 1.5 किलो प्रतिदिन व भैंस के लिए 2 किलो प्रतिदिन होती है।

● **उत्पादन के लिए आहार–** उत्पादन आहार पशु की वह मात्रा है जिसे कि पशु को जीवन निर्वाह के लिए दिए जाने वाले आहार के अतिरिक्त उसके दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है। जीवन निर्वाह के अतिरिक्त गाय को प्रत्येक 2.5 लीटर दूध के पीछे 1 किलो दाना तथा भैंस को प्रत्येक 2 लीटर दूध के पीछे 1 किलो दाना दें। यदि हर चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो हर 10 किलो अच्छे किस्म के हरे चारे को देकर 1 किलो दाना कम किया जा सकता है। इससे पशु आहार की कीमत कुछ कम हो जाएगी और उत्पादन भी ठीक बना रहेगा। पशु को दुग्ध उत्पादन तथा आजीवन निर्वाह के लिए साफ पानी दिन में कम से कम तीन बार जरूर पिलायें।

● **गर्भवस्था के लिए आहार**–पशु की गर्भवस्था में उसे 5वें महीने से अतिरिक्त आहार दिया जाता है क्योंकि इस अवधि के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि बहुत तेजी के साथ होने लगती है। अतः गर्भ में पल रहे बच्चे की उचित वृद्धि व विकास के लिए तथा गाय/भैंस के अगले ब्यांत में सही दुग्ध उत्पादन के लिए इस आहार का देना नितान्त आवश्यक है। 5 महीने से ऊपर की गाभिन गाय या भैंस को 1 से 1.5 किलो दाना प्रतिदिन जीवन निर्वाह के अतिरिक्त दें।

● **बछड़े या बछड़ियों के लिए–** 1 किलो से 2.5 किलो तक दाना प्रतिदिन उनकी उम्र या वजन के अनुसार दें।

● बैलों के लिए- खेतों में काम करने वाले बैलों के लिए 2 से 2.5 किलो प्रतिदिन, बिना काम करने वाले बैलों के लिए 1 किलो प्रतिदिन।

## गाय या भैंस का संतुलित दाना मिश्रण कैसे बनायें

पशुओं के दाना मिश्रण में काम आने वाले पदार्थों का नाम जान लेना ही काफी नही है। क्योंकि यह ज्ञान पशुओं का राशन परिकलन करने के लिए काफी नही है। एक पशुपालक को इस से प्राप्त होने वाले पाचक तत्वों जैसे कच्ची प्रोटीन, कुल पाचक तत्व और चयापचयी उर्जा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तभी भोज्य में पाये जाने वाले तत्वों के आधार पर संतुलित दाना मिश्रण बनाने में सहसयता मिल सकेगी। नीचे लिखे गये किसी भी एक तरीके से यह दाना मिश्रण बनाया जा सकता है, परन्तु यह इस पर भी निर्भर करता है कि कौन सी चीज सस्ती व आसानी से उपलब्ध है।

## संतुलित आहार न खिलाने पर पशुओं को होने वाली हानियां

● बछड़े व बछियों की वृद्धि दर कम हो जाती है, जिसके उनकी परिपक्वता में देरी होती है।

● कार्य हेतु जाने वाले पशुओं की कार्यक्षमता कम हो जाती है।

● संतुलित आहार के अभाव में पशुओं में कमजोरी आने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।

● सांडों में कम उत्तेजना, शुक्राणुओं में निष्क्रियता, गायों में गर्मी में न आना व गर्भधारण में देरी संतुलित आहार के आभाव में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे पशुओं के गर्भधारण करने पर बछड़ा अस्वस्थ व कमजोर होता हैं तथा कभी–कभी गर्भपात की संभावना भी प्रबल रहती है। संतुलित आहार के आभाव में पशुओं में दुग्ध उत्पादन दिन प्रतिदिन कम होता जाता है जो आर्थिक दृष्टि से अति आवश्यक महत्वपूर्ण है।

## डायरेक्ट सीडेड राइस में निवेश से

# जलवायु-अनुकूल भारतीय कृषि का बदला जा सकता है भविष्य

**हैदराबाद। देश की धान खेती आज कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। सिंचाई जल की कमी, खेतिहर मजदूरी की बढ़ती लागत और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों ने पारंपरिक रोपाई-आधारित धान खेती (टीपीआर) को दिन-प्रतिदिन महँगा और जोखिमपूर्ण बना दिया है। ऐसे समय में सूखी डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR) एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभर रही है।**

हालाँकि, अब तक डीएसआर को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई है, क्योंकि प्रचलित धान की अधिकांश किस्में सीधे बोआई के लिए विकसित नहीं की गई थीं।इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान (IRRI) द्वारा भारतीय अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से तथा भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के समर्थन से एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि यदि डीएसआर-अनुकूल किस्मों के विकास में लक्षित निवेश किया जाए, तो किसानों और पर्यावरण—दोनों को ठोस लाभ मिल सकते हैं।

### खेतों में दिखा डीएसआर का मजबूत प्रदर्शन

सूखी डायरेक्ट सीडेड परिस्थितियों में की गई बड़े पैमाने की फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन में नई धान लाइनों ने समान अंकुरण, तेज शुरुआती वृद्धि और मजबूत पौध विकास दिखाया। इससे स्पष्ट हुआ कि ये किस्में कम पानी और कम श्रम में भी अच्छी उपज देने की क्षमता रखती हैं।

आईआरआरआई की धान प्रजनक डॉ. पल्लवी सिन्हा ने कहा,-'डायरेक्ट सीडेड धान तभी सफल हो सकती है, जब किसान उस पर हर साल भरोसा कर सकें। निरंतर निवेश से ही ऐसी किस्में विकसित होती हैं जो अलग-अलग परिस्थितियों में स्थिर प्रदर्शन दें।'

### डीएसआर और रोपाई—दोनों के लिए उपयुक्त किस्में

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य यह रहा कि किसानों द्वारा पहले से पसंद की जाने वाली धान किस्मों को इस तरह सुधारा जाए कि वे डायरेक्ट सीडेड और पारंपरिक रोपाई—दोनों परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकें।

कई मौसमों तक किए गए परीक्षणों में पाया गया कि श्रेष्ठ डीएसआर-अनुकूल लाइनों ने डायरेक्ट सीडेड दशा में लगभग 15 प्रतिशत अधिक उपज दी, जबकि रोपाई की स्थिति में भी उनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा।इस दोहरी अनुकूलता से किसानों को जल संकट, मजदूरों की कमी और मौसम की अनिश्चितता के बीच खेती के तरीके चुनने की आज़ादी और सुरक्षा मिलती है।

खेत में किए गए तुलनात्मक प्रदर्शन में यह भी देखा गया कि एक नई डीएसआर-अनुकूल लाइन ने, डायरेक्ट सीडेड परिस्थितियों में, प्रचलित हाइब्रिड किस्म की तुलना में बेहतर बढ़वार दिखाई।

आईआरआरआई के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रजनन प्रमुख डॉ. विकास के. सिंह ने कहा,-'अगर किस्में भरोसेमंद नहीं होंगी, तो किसान डीएसआर नहीं अपनाएँगे। लोकप्रिय किस्मों को डायरेक्ट सीडिंग के अनुकूल बनाकर हम किसानों को कम पानी और कम श्रम में बेहतर उत्पादन दिला सकते हैं।'

### जलवायु लक्ष्यों से सीधा जुड़ाव

वैज्ञानिकों का मानना है कि डीएसआर का विस्तार भारत की वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं—जैसे उत्सर्जन तीव्रता में कमी और कृषि में जल-उपयोग दक्षता—के साथ पूरी तरह मेल खाता है।

डीबीटी के वैज्ञानिक एवं परियोजना अधिकारी डॉ. संजय कालिया ने कहा,-'धान की खेती में मीठे पानी को अक्सर मुफ़्त संसाधन मान लिया जाता है। डीएसआर तकनीक इस सोच को बदलेगी। हमारा लक्ष्य है कि धान की खेती भी गेहूँ की तरह हो—और अगले एक दशक में यह हकीकत बन सकती है।'

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि डीएसआर-अनुकूल किस्मों को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए, तो मध्य भारत के धान उत्पादक राज्यों में सिंचाई जल की मांग में भारी कमी, किसानों की आय में बढ़ोतरी और धान खेती के कार्बन फुटप्रिंट में गिरावट संभव है। अध्ययन में शामिल कई नई किस्में इस समय राष्ट्रीय परीक्षण प्रक्रिया के अंतिम चरणों में हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा निवेशों का लाभ जल्द ही किसानों के खेतों में दिखाई देगा।

बढ़ते जलवायु जोखिमों के दौर में, डायरेक्ट सीडेड राइस में निवेश केवल एक कृषि तकनीकी निर्णय नहीं, बल्कि भारतीय कृषि को अधिक टिकाऊ, सुरक्षित और भविष्य-सक्षम बनाने की रणनीतिक पहल है। यह डीबीटी-समर्थित अध्ययन अंतरराष्ट्रीय जर्नल The Plant Genome में प्रकाशित हुआ है।

# समर्थन मूल्य पर सात मार्च तक होगा गेहूं खरीदी के लिये पंजीयन : मुख्यमंत्री

**भोपाल ( कृषक जगत )।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं खरीदी के लिये पंजीयन 7 फरवरी से आरंभ हो गया है, यह 7 मार्च तक जारी रहेगा। प्रदेश में 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य गत वर्ष से 160 रुपए अधिक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक संदेश मिला है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में जल गंगा अभियान आरंभ हो जाएगा जो 3 महीने तक जारी रहेगा। उन्होंने मंत्रीगण को अपने-अपने जिलों में अभियान की गतिविधियों के व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डॉ. यादव ने बताया कि धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपए रखा गया है, जो पिछली बार की एमएसपी से अधिक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 51 लाख 74 हजार मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ। प्रदेश में 8 लाख 59 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया, जिसमें से 7 लाख 89 हजार से अधिक किसानों ने स्पॉट बुकिंग कर धान उत्पादन में अपना योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा इस वर्ष प्रदेश में गेहूं की पर्याप्त पैदावार होने की संभावना है, राज्य सरकार के पास भंडारण की समुचित व्यवस्था है।

### अब तक 20 हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन

रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये अब तक 20 हजार 98 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से अपील की है कि निर्धारित समय में पंजीयन अवश्य करा लें। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि अभी तक इंदौर संभाग में 4084, उज्जैन में 9524, ग्वालियर में 476, चम्बल में 123, जबलपुर में 788, नर्मदापुरम में 900, भोपाल में 3602, रीवा में 68, शहडोल में 83 और सागर में 450 किसानों ने पंजीयन कराया है।

# गेहूं के सीमित निर्यात को मंजूरी

## मजबूत भंडार और बेहतर रबी परिदृश्य के बीच भारत का संतुलित कदम

**( ग्लोबल एग्रीकल्चर डेस्क )**

**नई दिल्ली। करीब चार वर्षों के प्रतिबंध के बाद भारत सरकार ने नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के निर्यात को मंजूरी दी है। यह निर्णय किसान संगठनों और व्यापारिक संस्थाओं की लगातार उठ रही मांग के बाद लिया गया है, जो बढ़ती घरेलू उपलब्धता और अधिक आवक के समय कीमतों में गिरावट की आशंका को लेकर चिंतित थे।**

**निर्यात नियंत्रण के वर्षों बाद नीतिगत बदलाव**- सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना और घरेलू बाजार में संतुलन बनाए रखना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्यात की अनुमति सीमित मात्रा में दी गई है ताकि देश की खाद्य सुरक्षा पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। इसे पूर्ण उदारीकरण के बजाय एक सावधानीपूर्वक पुनः प्रवेश के रूप में देखा जा रहा है।

**पर्याप्त घरेलू भंडार से बढ़ा भरोसा**- यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब देश में गेहूं की उपलब्धता उल्लेखनीय रूप से बेहतर हुई है। वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र के पास लगभग 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं का भंडार उपलब्ध होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 32 लाख मीट्रिक टन अधिक है। यह स्थिति दर्शाती है कि सरकारी खरीद प्रणाली के बाहर भी बाजार में पर्याप्त आपूर्ति मौजूद है।

इसी के साथ भारतीय खाद्य निगम के केंद्रीय पूल में गेहूं का भंडार भी मजबूत बना हुआ है। 1 अप्रैल 2026 तक केंद्रीय भंडार लगभग 182 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो बफर मानकों से काफी अधिक है। पर्याप्त स्टॉक को देखते हुए सरकार का मानना है कि सीमित निर्यात से न तो घरेलू आपूर्ति प्रभावित होगी और न ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दबाव पड़ेगा।

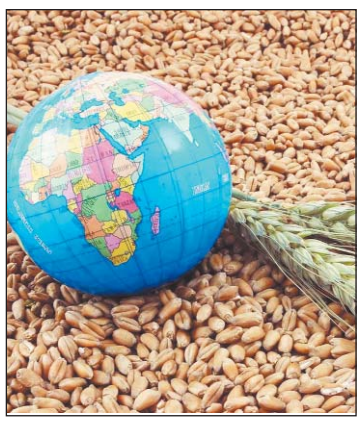

**बढ़ा रकबा, मजबूत उत्पादन की उम्मीद**- रबी 2026 में गेहूं का रकबा बढ़कर 334.17 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 328.04 लाख हेक्टेयर था। बुवाई क्षेत्र में यह वृद्धि और अब तक अनुकूल फसल परिस्थितियों ने बेहतर उत्पादन की उम्मीद को मजबूत किया है। ऐसे परिदृश्य में निर्यात की अनुमति को अतिरिक्त उत्पादन को समाहित करने और अधिक आवक के समय कीमतों में गिरावट को रोकने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है।

**2022 के प्रतिबंध से वैश्विक बाजार में संतुलित वापसी तक**- मई 2022 में भीषण गर्मी के कारण उत्पादन प्रभावित होने और घरेलू उपलब्धता घटने की आशंका के चलते भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी समय रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में तेज उछाल आया। घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उस समय निर्यात पर रोक आवश्यक मानी गई थी।

वर्तमान परिस्थितियां उससे भिन्न हैं। बेहतर उत्पादन संभावना, पर्याप्त भंडार और अपेक्षाकृत स्थिर मूल्य स्थिति के बीच सरकार ने नियंत्रित मात्रा में निर्यात की अनुमति देकर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। यह कदम किसानों के हित, मुद्रास्फीति प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है, साथ ही भारत को वैश्विक गेहूं बाजार में सीमित रूप से पुनः सक्रिय करने की दिशा में भी संकेत देता है।

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय घरेलू आपूर्ति और उत्पादन को लेकर नीति-निर्माताओं के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। आने वाले महीनों में अंतिम उत्पादन अनुमान, खरीद की स्थिति और मूल्य प्रवृत्तियां तय करेंगी कि क्या भविष्य में निर्यात पर और ढील दी जाएगी।

## फोटो गैलरी

स्वागत

**राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा का लोकभवन भोपाल में स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया।**

मुलाकात

**आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। इस दौरान राज्य में कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों, योजनाओं की प्रगति तथा भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू भी उपस्थित थे।**

उत्साहवर्धन

**मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दमोह के नोहटा में नोहलेश्वर महोत्सव मेले में आयोजित प्रदर्शनी में स्थानीय पारंपरिक कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।**

डायरी भेंट

**केन्द्रीय फार्म एवं मशीनरी प्रशिक्षण संस्थान ( भारत सरकार ) बुधनी में विशेषज्ञ डॉ. रणजीत पवार को कृषक जगत डायरी भेंट करते हुए प्रकाश दुबे। समीप हैं संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. ए. के. उपाध्याय।**

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

# पशुपालन मंत्री ने गोटवाला फार्म का किया भ्रमण

धार

**धार (कृषक जगत)।** ग्राम सुंद्रेल स्थित गोटवाला फार्म मध्यप्रदेश की सबसे पुरानी बकरी पालन एवं प्रजनन केंद्र इकाई का गत दिनों मप्र शासन के पशुपालन विभाग (स्वतंत्र प्रभार) के मंत्री श्री लखन पटेल द्वारा भ्रमण किया गया। इस अवसर पर फार्म के संस्थापक श्री दीपक पाटीदार (भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय 'बकरी पंडित' पुरस्कार से सम्मानित) द्वारा संचालित उन्नत नस्लों की बकरी पालन इकाई का मंत्री ने अवलोकन किया। भ्रमण के दौरान सिरोही, सोजत, बीटल, करौली, बरबरी सहित अन्य नस्लों की गुणवत्ता, प्रजनन प्रणाली एवं वैज्ञानिक प्रबंधन मॉडल की जानकारी प्राप्त की।

श्री पटेल ने फार्म में विकसित जीरो वेस्टेज मॉडल का भी निरीक्षण किया, जिसमें बकरी के मैंगनी/मल से वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर ऑर्गेनिक सब्जी उत्पादन सहित संसाधनों के समुचित उपयोग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस दौरान श्री दीपक पाटीदार से मध्यप्रदेश में बकरी पालन की संभावनाओं, इसके विस्तार, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तथा शासन एवं उद्यमियों के संयुक्त सहयोग से पीपीपी मॉडल विकसित करने पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके पश्चात श्री पटेल ने शिव नर्सरी का भ्रमण किया, जहाँ नर्सरी के संस्थापक श्री शिवजी पाटीदार द्वारा संपूर्ण नर्सरी की विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में जिले के उप संचालक पशुपालन डॉ. आर. एस. सिसोदिया सहित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

# श्री ओझा को मिला जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार

**शिवपुरी (कृषक जगत)।** गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिवपुरी जिले के युवा पशुपालक श्री वीरू ओझा को पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना के द्वारा जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार में राशि रु 25000 सह प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। श्री ओझा ने इस सफलता का श्रेय स्वयं की सोच पिता श्री रामनारायण ओझा का सहयोग और जिले में कृषि विज्ञान केंद्र, पशुपालन विभाग शिवपुरी से समय-समय पर प्रेरणा मार्गदर्शन एवं परामर्श को दिया है। श्री वीरू ने पशुपालन के क्षेत्र में ट्रिपल एस तकनीक (सेक्स सोर्टेड सीमेन) जिसमें उन्नत दुधारू नस्ल की साहीवाल एवं गिर गाय की 2 बछड़ी तैयार की है। इनकी सफलता में जिला प्रशासन का प्रोत्साहन, संबंधित विभागों का समन्वय और कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी के प्रमुख डॉ. पुनीत कुमार के निर्देशन में डॉ. एम. के. भार्गव वरिष्ठ वैज्ञानिक चारा तकनीकियों से जोड़ना एवं समस्त स्टॉफ द्वारा प्रशिक्षित कराना प्रमुख है।

शिवपुरी

## उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाएं

### पीएमएफएमई योजना की जानकारी
**प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई)**

**योजना:** प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई)

**पात्रता एवं मापदंड :** व्यक्तिगत/समूह श्रेणी-व्यक्तिगत, स्वामित्व वाली फर्मों, साझेदारी फर्मों, एफपीओ, एनजीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा पूर्व से संचालित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन एवं नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपये तक का प्रावधान।

**कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर :** किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनियाँ (एफपीसी, सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूह, फेडरेशन एवं सरकारी एजेंसियों के लिए 35 प्रतिशत क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसमें अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये होती है। यह सहायता सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, लैब्स, इनक्यूबेशन सेंटर, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रदान की जाती है। निजी एवं समूह के हितग्राही, दोनों के लिए अनुदान सहायता में परियोजना लागत में संयंत्र और मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत शामिल है लेकिन भूमि/किराये या पट्टा अथवा कार्य शेड की लागत शामिल नहीं होगी। तकनीकी सिविल कार्य एलिजिबल परियोजना लागत के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी हितग्राही की होगी।

**आवेदन कैसे करें :** भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित एमआईएस के पोर्टल पर हितग्राही स्वयं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सहायता के लिए जिलों में जिला रिसोर्स पर्सन्स (डीआरपी) नियुक्त किये गए हैं।

**लाभ की राशि:** परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपये तक का प्रावधान।

**लाभ राशि के वितरण की आवृत्ति :** अनुदान की एकमुश्त राशि हितग्राही के ट्रांसिएंट खाते में स्थानांतरित की जाती है एवं 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत हितग्राही को प्रदान की जाती है।

**स्त्रोत : जनसंपर्क विभाग म.प्र. के प्रकाशन 'नई राहें नए अवसर' से उद्धृत।**

# कैलाश ने पथरीली भूमि में जी-9 केले की खेती से रचा नवाचार

**छिन्दवाड़ा (कृषक जगत)।** छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम भुताई के प्रगतिशील किसान श्री कैलाश पवार ने नवाचार के माध्यम से कृषि क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश की है। श्री पवार ने लगभग 18 एकड़ क्षेत्र में केले की उन्नत किस्म जी-9 की खेती कर यह साबित कर दिया है कि कठिन मानी जाने वाली भूमि में भी आधुनिक तकनीक के सहारे बेहतर उत्पादन संभव है। उन्होंने गत वर्ष अप्रैल माह में पुणे से जी-9 किस्म के पौधे मंगवाकर ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ रोपण किया था, जो मात्र लगभग 11 माह में पूरी तरह तैयार हो गई है।

छिंदवाड़ा

किसान श्री पवार के अनुसार 15 फरवरी के बाद मार्च माह तक पूरी फसल की कटाई हो जाएगी और प्रति एकड़ ढाई से तीन लाख रुपये तक लाभ होने की संभावना है। फसल की गुणवत्ता को देखते हुए जबलपुर एवं नागपुर के व्यापारियों ने खेत पर पहुंचकर निरीक्षण किया है तथा वे सीधे खेत से ही उपज खरीदने के लिए संपर्क कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि यह केला पथरीली एवं मुरम वाली उस भूमि पर उगाया गया है, जहाँ सामान्यत: अन्य फसलें लेना संभव नहीं माना जाता।

कृषि विभाग की टीम ने भी खेत पर पहुँचकर इस नवाचार का अवलोकन किया और किसान द्वारा अपनाई गई तकनीकों की सराहना की। उल्लेखनीय है कि श्री कैलाश पवार पूर्व से ही नवाचारी किसान रहे हैं। उन्होंने पिछले वर्ष लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती कर अच्छा लाभ अर्जित किया था। वर्तमान वर्ष में भी उन्होंने 6 एकड़ में स्ट्रॉबेरी, एक एकड़ में ब्लूबेरी तथा एक एकड़ में गोल्डन बेरी की खेती की है, जिसकी उपज 15 फरवरी के बाद बाजार में आने की संभावना है। श्री कैलाश पवार की यह पहल क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत है, जो यह संदेश देती है कि नवाचार, तकनीक और मेहनत के साथ कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है।

## राजगढ़ के खेतों में ड्रोन क्रांति

# 2500 एकड़ में ऐतिहासिक स्प्रे

**राजगढ़ (कृषक जगत)।** कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में परंपरागत खेती के तौर-तरीकों को पीछे छोड़ते हुए राजगढ़ जिले के किसानों ने आधुनिक कृषि की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। अंकुरण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मऊ ने जिले में पहली बार ड्रोन तकनीक का उपयोग कर 2500 एकड़ भूमि पर फसलों का उपचार (स्प्रे) कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

साथ ही अंकुरण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के संचालक श्री श्याम राजपूत ने बताया कि कृषि ड्रोन का उपयोग केवल एक नवाचार नहीं, बल्कि किसानों की बड़ी समस्याओं का समाधान है। इसके प्रमुख लाभ है। जिनमें समय की भारी बचत घंटों का काम अब चंद मिनटों में पूरा हो रहा है। समान छिड़काव सेंसर आधारित तकनीक से पूरी फसल पर एक समान दवा का छिड़काव होता है, जिससे बर्बादी रुकती है।

कंपनी के तकनीकी ऑपरेटर श्री नीरज राजपूत ने साझा किया कि इस रबी सीजन में टीम ने 3 अत्याधुनिक ड्रोन की मदद से सरसों, चना और मसूर जैसी फसलों को कवर किया है। 2500 एकड़ का यह सफर तो महज एक शुरुआत है। 'हमारा लक्ष्य अगले साल 10,000 एकड़ तक पहुंचना है। रबी के साथ-साथ खरीफ सीजन में सोयाबीन और मक्का जैसी फसलों पर भी ड्रोन स्प्रे के परिणाम काफी उत्साहजनक होने वाले हैं।'

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सारंगपुर श्री राजेश राजपूत ने बताया कि कृषि ड्रोन तकनीक का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन उत्साहजनक है। खेतों में ड्रोन से फसलों पर छिड़काव के काफी सकारात्मक और प्रभावी परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

उपसंचालक कृषि श्री सचिन जैन ने कहा कि 'राजगढ़ जिले में ड्रोन तकनीक के माध्यम से किया जा रहा यह नवाचार कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहा है। तकनीक के इस समावेश से निश्चित ही हमारे जिले के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ-साथ आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपना रहे हैं। शासन की मंशा के अनुरूप यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा।' अंकुरण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का यह प्रयास न केवल राजगढ़ के किसानों को सशक्त बना रहा है, बल्कि 'डिजिटल एग्रीकल्चर' के सपने को धरातल पर उतार रहा है। यह तकनीक आने वाले समय में लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी।

# समस्या -समाधान

**समस्या– टमाटर की खेती पहली बार कर रहा हूं टमाटर फट रहे हैं, उपाय बतायें।**

**– प्रेमनारायण लोधी**

**समाधान** ● टमाटर में फल फटने के कई कारण हैं। बहुधा फल अनियमित व अव्यवस्थित सिंचाई के कारण भी फटते हैं। न्यूनतम तथा अधिकतम तापक्रम में अधिक उतार–चढ़ाव भी फल फटने का कारण बनता है। खेत में पलवार (मल्च) बिछाने से फटने वाले फलों को रोका जा सकता है।

● फसल में अधिक नत्रजन तथा कम पोटाश देने के कारण भी फल फटते हैं। सुनिश्चित करिये कि आप के खेत में पर्याप्त जैविक पदार्थ है जो तत्वों के पौधों द्वारा अवशोषण में सहायक होता है। संतुलित खाद का उपयोग करें।

● यदि आपने टमाटर अधिक चूना वाली या हल्की दोमट मिट्टी में लगायें हैं तो ऐसी भूमि में सामान्यतः बोरान नामक तत्व की कमी पाई जाती है जिसके कारण भी फल फटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बोरान की पूर्ति के लिए 0.3 से 0.4 प्रतिशत बोरेक्स के घोल का छिड़काव करें। रोपाई के 4 सप्ताह बाद छिड़काव करने से अधिक लाभ मिलता है।

**समस्या– प्याज की पत्तियां ऊपर से सूख रही हैं। कन्द नहीं बन पा रहे हैं, उपाय बतायें।**

**– अमित कुशवाह**

**समाधान** ● यदि आपके खेत में प्याज की पत्तियां ऊपर से पीली पड़कर सूख रही हैं तो यह पोटाश की कमी के कारण हो सकता है। पोटाश की कमी के कारण पुरानी पत्तियां पूर्ण रूप से सूख कर झड़ भी सकती हैं। ऊपरी भाग में पीलापन आ जाता है।

● प्याज की फसल को पोटाश की मात्रा अधिक लगती है। जहां इसे 100 किलो नत्रजन व 50 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर लगता है, वहीं पोटाश की भी 100 किलो प्रति हेक्टेयर मात्रा की इसे आवश्यकता होती है। इनके अतिरिक्त इस फसल को गंधक की भी आवश्यकता होती है। यह हो सकता है। आपने पोटाश की मात्रा कम दी हो।

● पोटाश की कमी के कारण कंद अच्छे नहीं पड़ेंगे तथा उनका छिलका भी पतला रह जाता है। यदि यह लक्षण हो तो आप घुलनशील पोटाश का छिड़काव कर देख लें। परिणाम आपको नई पत्तियों में ही दिखाई देंगे।

● फसल कटाई के बाद खेत से मिट्टी के नमूने लेकर मिट्टी की जांच करा लें, ताकि भविष्य में आप संतुलित उर्वरक की आवश्यकता अनुसार डाल सकें।

**समस्या– कटहल में बहुत कम फूलों में ही फल लगते हैं, क्या कारण है?**

**– खुशीलाल**

**समाधान** ● कटहल के पेड़ों में नर व मादा फूल अलग–अलग होते हैं। सिर्फ मादा फूलों में ही फल लगते हैं। नर फूलों में नहीं, फूलों में फल लगने का यही कारण हैं।

● इसकी पहचान के लिए यह ध्यान रखें कि नर फूल पौधे की नई कोमल टहनियों में लगते हैं यह पत्ती के साथ या मादा फूलों के ऊपर लगते हैं। नर फूलों में पीले चिपचिपे परागकण देखे जा सकते हैं। जिनसे मीठी सुगंध निकलती है जिसमें कीट आकर्षित होते हैं। यह 5 से 10 से.मी. लम्बे व 20 से 45 से.मी. चौड़े रहते हैं। इनके बांझ फूल भी रहते हैं।

● मादा फूल नर फूलों से बड़े रहते हैं वह मोटे–छोटे डंठल से पौधे के पुराने तनों तथा मुख्य तने से निकलते हैं। ये बेलनाकार 5 से 15 से.मी. लम्बे व 3.0 से 4.5 से.मी. चौड़े रहते हैं। मादा फूल ही फल में परिवर्तित होते हैं। इस कारण कटहल में बहुत कम फूलों में ही फल लगते हैं।

**समस्या– सब्जी के लिए फ्रेन्चबीन (राजमा) की फसल पहली बार लगाना चाहता हूं।**

**– प्रेमनारायण**

**समाधान** ● फ्रेन्चबीन की फसल लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती हैं। मिट्टी का पी.एच. मान 5.3 से 6.0 हो तो उपयुक्त रहेगा। परन्तु यह फसल अधिक तापक्रम तथा पाले से बहुत अधिक प्रभावित होती है। इसके लिए भूमि का तापक्रम 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बढ़वार के लिए उपयुक्त रहता है।

● इसकी दो ऋतुएं जून–जुलाई और जनवरी–फरवरी में की जा सकती है। बीज की मात्रा 16–20 किलोग्राम प्रति एकड़ लगेगी। बीज वीटावैक्स से उपचारित कर ही बोयें (3 ग्राम प्रति किलो बीज)।

● इसकी जातियां दो प्रकार की रहती हैं। झाड़ीनुमा पौधों की जातियों में पूसा पार्वती, अर्का कोमल, पेन्सिल वन्डर, जम्प प्राइडर प्रमुख हैं। बेल वाली जातियों में व्ही.पी.एफ–191, प्रीमियर, फुले सुरेखा तथा केतुकी प्रमुख हैं।

● इस फसल में जड़ों में गांठें नहीं रहती जैसा कि अन्य दलहनी फसलों में होता है। जिनमें स्थित राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण से नत्रजन अवशोषित कर पौधों को उपलब्ध करते हैं।

## निवेदन

**समस्या-समाधान स्तंभ में पाठकों से निवेदन है कि अपनी खेती-किसानी संबंधी समस्या कृषि विशेषज्ञों से निराकरण करने हेतु वाट्सएप पर भेजें. एक बार में केवल एक प्रमुख समस्या ही वाट्सएप पर लिखकर भेजें. वाट्सएप हेल्पलाइन नं. 6262166222.**

**समस्या-समाधान**

**कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.)**
**फोन-0755-4248100,2554864**

## प्राकृतिक खेती – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

### रिसोर्स और सपोर्ट

**पोषण प्रबंधन में सूक्ष्म जीवाणुओं का क्या रोल है?**

माइक्रोब्स मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व और खनिज को पौधों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, बढ़वार को बढ़ावा देने वाले हॉर्मोन बना सकते हैं, पौधे के रोग प्रतिरोधक प्रणाली को उत्तेजित कर सकते हैं, और तनाव प्रतिक्रिया को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आमतौर पर, ज़्यादा अलग–अलग तरह के मिट्टी के माइक्रोबायोम से पौधों में कम बीमारियाँ होती हैं और ज़्यादा पैदावार होती है।

**ह्यूमस क्या है?**

ह्यूमस या धरण गहरे रंग का, जैविक मैटीरियल है जो पौधे और जानवरों के मैटीरियल के सड़ने से बनता है।

**मिट्टी में ह्यूमस कैसे बनता है?**

पौधे पत्तियाँ, टहनियाँ और दूसरी चीज़ें ज़मीन पर गिराते हैं। ये चीज़ें जमा होकर पत्तियों का कूड़ा बनाती हैं। जब जानवर मर जाते हैं, तो उनके बचे हुए हिस्से कूड़े में मिल जाते हैं। समय के साथ, यह सारा कूड़ा ह्यूमिफिकेशन नाम के प्रोसेस से अपने सबसे बेसिक केमिकल एलिमेंट्स में डीकंपोज़/टूट जाता है। ज़्यादातर जैविक कूड़े के डीकंपोज़ होने के बाद जो गाढ़ा भूरा या काला पदार्थ बचता है, उसे ह्यूमस कहते हैं। इस तरह ह्यूमिफिकेशन से बनने वाला ह्यूमस कंपाउंड्स पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों का मिक्सचर होता है।

**ह्यूमस मिट्टी के लिए कैसे फायदेमंद है?**

यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है क्योंकि इसमें स्वस्थ मिट्टी के लिए कई उपयोगी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यह मिट्टी से होने वाली बीमारियों को रोकने में मदद करता है। यह माइक्रो पोरोसिटी बढ़ाकर मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करता है। यह मिट्टी की अच्छी बनावट बनाने को बढ़ावा देता है और पौधों के न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता बढ़ाता है।

**गाय के मूत्र में कौन से पोषक तत्व होते हैं और यह प्राकृतिक खेती में मिट्टी के लिए कैसे फायदेमंद है?**

नाइट्रोजन, पोटैशियम और फॉस्फोरस से भरपूर न्यूट्रिएंट्स वाला गाय का मूत्र मिट्टी में मिलाने और सीधे इस्तेमाल करने या फॉर्मूलेशन और इस्तेमाल के लिए बहुत फायदेमंद है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा, सल्फर, सोडियम, मैंगनीज, आयरन, एंजाइम और क्लोरीन की मौजूदगी गाय के मूत्र को एक ज़रूरी प्राकृतिक पेस्ट रिपेलेंट बनाती है, जिसे सस्टेनेबल खेती के लिए कम बाहरी इनपुट की ज़रूरत होती है।

कृषक जगत

बागवानी सीरीज

साग-सब्जी उत्पादन उन्नत तकनीक
रु. 95
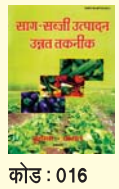
कोड : 016

सब्जियों में पौध संरक्षण
रु. 75

कोड : 017

मशरूम एक लाभ अनेक
रु. 45

कोड : 019

मिर्च की उन्नत खेती
रु. 55

कोड : 020

केला उत्पादन
रु. 70

कोड : 025

गुलाब
बहुरंगी संशोधित संस्करण
रु. 75

कोड : 027

पपीता
रु. 55

कोड : 031

अदरक
रु. 55

कोड : 032

फलों की खेती
रु. 75

कोड : 040

सजाएं फूलों से बगिया
रु. 65

कोड : 041

घर की बगिया
रु. 95

कोड : 050

डाक द्वारा मंगवाने हेतु निम्नलिखित जानकारी के साथ हमारे पते पर ड्राफ्ट/मनीऑर्डर के साथ ऑर्डर कीजिए . किताब कोड नं. पर ✔ निशान लगाएं

016 ☐ 017 ☐ 019 ☐ 020 ☐ 025 ☐ 027 ☐ 031 ☐ 032 ☐ 034 ☐ 040 ☐ 041 ☐ 050 ☐

नाम _____

ग्राम _____ पोस्ट _____ तह. _____

जिला _____ फोन/मोबा. _____

कुल राशि _____ ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या _____

संलग्न ड्राफ्ट नं. _____ मनी आर्डर रसीद क्र. _____ वी.पी. भेजें ☐

संस्थाओं द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां खरीदने पर आकर्षक छूट. अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें.

कृपया ड्राफ्ट या मनीआर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम
14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल – 462011
फोन : 0755-4248100, 2554864, मो.: 9826255861, Email-info@krishakjagat.org
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास, इंदौर (म.प्र.) मो. : 9826021837

स्वास्थ्य

# गाय का घी : महाऔषधि

वाग्भट द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की प्राचीनतम किताब अष्टांगहृदयं' में गाय के घी की गुणों का निम्नानुसार वर्णन किया गया है ।

शस्तंधिस्मिति मेधाग्नि बलायु :शुक्रचक्षुषाम। बाल वृद्ध प्रजाकांति सौकुमार्यस्वरार्थिनाम।।

क्षतक्षीण परिसर्पशस्त्राग्निग्लपितात्मनाम। वातपित्तविषोंन्मादशोषालक्ष्मीज्वरापहम।।

स्नेहानामुत्तमं शीतं वयसः स्थापनं परम। सहस्र वीर्य विधिभिर्धृतं कर्म सहस्र कृत।।

अर्थात बुद्धि, स्मृति (स्मरण शक्ति) , मेधा (धारणशक्ति वाली बुद्धि ), जठराग्नि, शारीरिक बल, दीर्घायु, शुक्र तथा दृष्टि के लिए उत्तम है ; बालको तथा वृद्धो के लिए श्रेष्ठ है। प्रजा (संतान), कांति, सुकुमारता तथा सुरीला या तेज स्वर चाहने वालों के लिए उत्तम है। क्षत, क्षीण (क्षय पीड़ित), विसर्पोगी, शस्त्रहत, अग्निदाह से पीड़ित रोगियों के लिए हितकर है। वातविकार, पित्तविकार, विषविकार, उन्माद, शोष (राजयक्ष्मा), अलक्ष्मी (निर्धनता या कुरूपता) तथा ज्वर का नाश करता है। यह समस्त स्नेह द्रव्यों में श्रेष्ट है, शीतवीर्य है, यौवन को स्थिर रखने वाले द्रव्यों में भी सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रोक्त विधियों से पकाकर रखा गया घी हजारों शक्तियों से पूर्ण होता है, अतएव युक्तियुक्त इसका प्रयोग करने पर यह हजारों चिकित्सोपयोगी कर्मो को सफल बनाता है।

स्नेह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है स्पर्श, प्रेम और देखभाल इत्यादि। स्नेह वह एहसास है जिससे आप महसूस करते है कि कोई आपकी परवाह करता है, आपको दुलारता है और आपको आराम देता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ स्नेहन के लिए चार पदार्थों की बात करते हैं (शरीर पर तैलीय पदार्थों का अनुप्रयोग): तैला (तेल), वसा (पशु वसा), मज्जा (अस्थि मज्जा) और घृत (घी) हैं। इनमें से, घृत (घी) को श्रेष्ठ माना जाता है। घी त्वचा को मुलायम और मजबूत बनाता है, सुरक्षा प्रदान करता है और त्वचा को पोषण देता है। घी शरीर की संपूर्ण शक्ति, चमक और सुंदरता को बढ़ाता है।

पिछले कई दशकों से विभिन्न गैर भारतीय संगठनो द्वारा घी को हृदय रोग का प्रमुख कारण मानते हुए इसका प्रयोग न करने के सम्बन्ध सुझाव दिए जाते रहे है। इसके कारण कुछ दशको से भारतीयों द्वारा घी का कम उपयोग किया जा रहा था। परिणामस्वरूप भारत में हृदय रोगियों की संख्या घटने के स्थान पर अन्य रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, रोग प्रतिरक्षा कम होना इत्यादि रोगियों कि संख्या में वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान वैज्ञानिक शोधो से यह स्पष्ट हो गया है कि हृदय के बिमारियों में घी का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है साथ ही घी में मौजूद कई विशेष गुणों के कारण अनेक रोगों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है।

आयुर्वेद चिकित्सा में गाय के घी का महत्वपूर्ण स्थान है। घी के चमत्कारिक गुणों के कारण इसे वर्षो तक सहेज कर रखने कि भी परंपरा थी। 100 वर्ष से अधिक पुराने घी को 'महाघृत' कहा जाता है जो कि बहुत मूल्यवान होता है, इसका उपयोग संनिपत्तज्वर, श्वास रोग आदि में उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गाय का घी शरीर से विषाक्त पदार्थो को बहार निकालने एवं दोषों को शांत करने में विशेष सहायक है। घी से झिल्ली एवं उत्तको को चिकनाइ एवं नमी प्राप्त होता है, यह उत्तको को क्षति से बचाता है एवं विषाक्त पदार्थो को शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है। पक्वाशय (बड़ी आंत) शरीर के पाचन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थो के विभिन्न अवयवो को अवशोषित कर शरीर के अन्य अंगो तक पहुँचाया जाता है। ज्यादातर बीमारियों का प्रारंभ पाचन तंत्र में किसी भी प्रकार की रुकावट आने से होता है। गाय का घी पाचन प्रणाली को चिकनाइ प्रदान कर पाचन शक्ति बढाने में मदद करता है। घी, पित्त (अग्नि) को संयमित रखने के साथ ही पाचक अम्लो को भी सन्तुलित करने में मदद करता है जिससे पाचन शक्ति बढती है।

मानसिक क्रियाप्रणाली जैसेए सीखना, स्मृति, याद को बढाने में गाय का घी बहुत मददगार है। पुराने शास्त्रों में गाय के घी को मेध्या रसायन कहा गया है जो चेतना एवं स्मृति के लिए लाभदायक है। आँखों की रौशनी, आवाज एवं बुधिमत्ता में भी गाय का घी सहायक है।

वर्तमान समय में पूरा विश्व कोविड 19 महामारी से ग्रसित है। इस महामारी काल में यह स्पष्ट हो गया है कि जिनमे रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है वह विभिन्न वायरस संक्रमणों से आसानी से रक्षा कर सकता है। आहार में नियमित रूप से गाय का घी सेवन करने से शरीर की रक्षा प्रणालियाँ सुचारू रूप से काम करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता सहज रूप से विकसित हो जाती है। बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य एवं बेहतर मानसिक विकास के लिए आहार में घी का नियमित उपयोग किया जाना आज के भागमभाग वातावरण में अपरिहार्य हो गया है। अतः गाय के घी का उपयोग लोगों को आहार में नियमित रूप से करना चाहिए ।

**भारत की प्राचीनतम दैवीय संस्कृति काल से गाय एवं उनके उत्पाद को पवित्रता, सम्पन्नता एवं जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। पुरातन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में गायो का विशेष स्थान था जिसके कारण वेद शास्त्रों में गायो की महिमा का वर्णन मिलता है। कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और अध्यात्मिक प्रगति में गाय का विशेष योगदान है। वर्तमान समय में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार गाय है। गाय के दुध को सम्पूर्ण भोजन भी माना गया है अर्थात दूध में मानव शरीर के पोषण के लिए आवश्यक समस्त अव्यय पाए जाते है। जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों के रस को सार रूप में शहद में परिवर्तित करती है उसी प्रकार गाय विभिन्न प्रकार के वनस्पति को खा कर, पाचन क्रिया द्वारा मंथन कर उसके सार भाग को दूध के रूप में परिवर्तित करती है। जिस प्रकार गाय के दुध, पौधों का सार है उसी प्रकार घी दुध का सार है। घी दूध में उसी प्रकार छिपा है जैसे इस सृष्टि में इश्वर। जिस प्रकार इश्वर को पाने के लिए अनेक जप तप करने पढ़ते है उसी प्रकार दूध से घी प्राप्त करने के लिए भी दूध के गुणों में मुलभुत परिवर्तन कर अर्थात पहले मीठे दूध को खट्टे दही में परिवर्तिब कर फिर उसे ठन्डे पानी के साथ मिलाकर मथने से मक्खन प्राप्त किया जाता है और इसी मक्खन को आग में तपाने से घी प्राप्त होता ळे अतः घी, गाय के दूध का सबसे उत्तम उत्पाद है।**

# सोया मिल्क शिशु के लिए फायदेमंद

अकसर मांओं को लगता है कि शिशु के लिए सोया मिल्क बेहतरीन विकल्प है। जबकि ऐसा नहीं है। आप जब भी अपने शिशु को सोया मिल्क की शुरुआत करें तो डाक्टर से संपर्क हमेशा करें। ध्यान रखें कि चाहे तमाम कंपनियां सोया मिल्क शिशु के जन्म से ही पीने लायक बना रही हों बावजूद इसके आपको सतर्क रहना जरूरी है। सामान्यतः विशेषज्ञ सोया मिल्क को 6 माह से कम आयु के बच्चों के लिए सोया मिल्क को तरजीह नहीं देते।

यदि आपके शिशु को गाय के दूध से एलर्जी हो तो आप सोया मिल्क को विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। लेकिन आपको यह बताते चलें कि सोया मिल्क एलर्जी न होने की गारंटी नहीं है। असल में यह जानना आवश्यक है कि आपके शिशु को किस प्रकार का दूध सूट करता है। यदि उसे पशु के दूध से एलर्जी है तो विशेषज्ञों की सलाह मुताबिक कब और कितना सोया मिल्क लेना है, यह अवश्य जान लें। आपको यह भी बताते चलें कि सामान्यतः शिशुओं को गाय के दूध से एलर्जी नहीं होती। अपने शिशु के लिए लो फैट सोया मिल्क को ही तरजीह दें।

यदि आप बिना किसी सलाह के अपने शिशु को सोया मिल्क पिला रही हैं तो ध्यान रखें कि कहीं यह समस्या का सबब न बन जाए। दरअसल सोया मिल्क में ओस्ट्रोजेन जैसे तत्व मसलन फाइटोएस्ट्रोजेन बहुतायत में पाए जाते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेन पौधों में प्राकृति रूप से मौजूद होते हैं। अतः सोया भी इसका अपवाद नहीं है। जो शिशु सोया मिल्क पर ही पूरी तरह निर्भर है सोया मिल्क के सेवन के चलते उनमें फाइटोएस्ट्रोजेन सम्बंधित बीमारी बढ़ने की आशंका हो जाती है। यह आपके शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है। सामान्यतः सोया मिल्क में ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो अन्य दूध में मौजूद न हो। इसके उलट सोया मिल्क के प्रतिदिन सेवन से शिशु के आने वाले दांतों को नुकसान हो सकता है। असल में सोया मिल्क में ग्लुकोस सिरप मौजूद होता है जो दांतों के लिए हानिकारक है। अतः शिशु को पानी अवश्य पिलाएं।

### सोते वक्त न दें

जैसा कि पहले ही जिक्र किया गया है कि सोया मिल्क शिशु के स्वास्थ्य के लिए कोई खास लाभकर नहीं है। लेकिन रात को सोते वक्त सोया मिल्क कतई न दे। यह आपके शिशु को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कोशिश करें कि सोया मिल्क हमेशा कप में दें। यह भी ध्यान रखें कि यदि आपने यह दूध बोतल में दिया है तो शिशु बोतल के निप्पल से ज्यादा देर तक न खेले। सोया मिल्क पर आश्रित शिशुओं के प्रति अतिरिक्त सजग रहना जरूरी है।

# सेहत के नुस्खे

हम यहां कुछ ऐसे पौष्टिक पदार्थों की जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक के लोग सेवन कर लाभ उठा सकते हैं और बलवान बन सकते हैं-

- सोते समय एक गिलास मीठे गुनगुने गर्म दूध में एक चम्मच शुद्ध घी डालकर पीना चाहिए.
- दूध की मलाई तथा पिसी मिश्री जरूरत के अनुसार मिलाकर खाना चाहिए, यह अत्यंत शक्तिवर्धक है.
- बादाम को घिसकर दूध में मिलाकर खाना चाहिए, यह अत्यंत शक्तिवर्धक है.
- छाछ से निकाला गया ताजा मक्खन तथा मिश्री मिलाकर खाना चाहिए, ऊपर से पानी न पिएं.
- 50 ग्राम उड़द की दाल आधा लीटर दूध में पकाकर खीर बनाकर खाने से अपार बल प्राप्त होता है. यह खीर पूरे शरीर को पुष्ट करती है.
- प्रातः एक पाव दूध तथा दो-तीन केले साथ में खाने से बल मिलता है, क्रांति बढ़ती है.
- एक चम्मच असगंध चूर्ण तथा एक चम्मच मिश्री मिलाकर गुनगुने एक पाव दूध के साथ प्रातः व रात को सेवन करें, रात को सेवन के बाद कुल्ला कर सो जाएं. 40 दिन में परिवर्तन नजर आने लगेगा.
- सफेद मूसली या धोली मूसली का पावडर, जो स्वयं कूटकर बनाया हो, एक चम्मच तथा पिसी मिश्री एक चम्मच लेकर सुबह व रात को सोने से पहले गुनगुने एक पाव दूध के साथ लें.
- सुबह-शाम भोजन के बाद सेवफल, अनार, केले या जो भी मौसमी फल हों, खाएं.

## पाक्षिक पंचांग

**16 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक**
**विक्रम संवत् 2082**
**फाल्गुन कृष्ण 14 से फाल्गुन शुक्ल 13 तक**

| दि. | माह | वार | | तिथि/त्यौहार |
|---|---|---|---|---|
| 16 | फरवरी | सोम | फाल्गुन कृष्ण | 14 |
| 17 | फरवरी | मंगल | ---------- | 30 अमावस्या पंचक 9.30 दिन से |
| 18 | फरवरी | बुध | फाल्गुन शुक्ल | 1 पंचक |
| 19 | फरवरी | गुरु | ---------- | 2 पंचक |
| 20 | फरवरी | शुक्र | ---------- | 3 पंचक |
| 21 | फरवरी | शनि | ---------- | 4 विनायकी चतुर्थी, पंचक समाप्त 8.12 रात्रि |
| 22 | फरवरी | रवि | ---------- | 5 |
| 23 | फरवरी | सोम | ---------- | 6 |
| 24 | फरवरी | मंगल | ---------- | 7/8 होलाष्टक प्रारंभ |
| 25 | फरवरी | बुध | ---------- | 9 |
| 26 | फरवरी | गुरु | ---------- | 10 |
| 27 | फरवरी | शुक्र | ---------- | 11 आमलकी एकादशी |
| 28 | फरवरी | शनि | ---------- | 12 |
| 01 | मार्च | रवि | ---------- | 13 प्रदोष व्रत |

## इफको की गतिविधियां

# इफको सकंट हरण बीमा को अपनाएं किसान

**छतरपुर ( कृषक जगत )।** इफको द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में नैनो उर्वरक उपयोगिता आधारित सहकारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक सीईओ श्री शिवम् शाह विशेष रूप से उपस्थित थे। सहकारिता प्रशिक्षण कार्यक्रम में इफको के क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री इंदर सिंह मेवाड़ा ने सम्बोधित करते हुए इफको नैनो उर्वरकों, जैव उर्वरकों, सागरिका उत्पाद व इफको संकट हरण बीमा योजना आदि को विस्तार से बताया। श्री शाह ने सभी समिति प्रबंधकों को इफको नैनो उर्वरक का स्वयं उपयोग करके देखने एवं ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसके लाभ एवं उपयोग पर जानकारी देने की बात कही। कार्यक्रम में श्री प्रमोद तिवारी खाद प्रभारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा सभी समिति प्रबंधकों को नैनो उर्वरक का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने की सलाह दी।

# इफको का आदान वितरण कार्यक्रम

**धार ( कृषक जगत )।** जिले के ग्राम ढोलाना में इफको ने कृषक संगोष्ठी आयोजित कर नैनो उर्वरकों की उपयोग विधि एवं लाभ तथा रासायनिक उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तृत रूप से किसानों से चर्चा की। इफको के अन्य उत्पादों की जानकारी भी सांझा की गई। इफको प्रतिनिधि ने संकट हरण योजना एवं ड्रोन के माध्यम से उर्वरक के छिड़काव पर भी किसानों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में 10 किसानों को प्याज फसल हेतु क्रान्तिक आदान किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में ग्राम के किसान उपस्थित रहे।

# नरवाई प्रबंधन पर कृषक संगोष्ठी

## बेहतर खेती के लिए नरवाई प्रबंधन पर दी महत्वपूर्ण जानकारी

**सिवनी।** कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग सिवनी के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय नरवाई प्रबंधन एवं रबी फसलों

में समसामयिक प्रबंधन विषय पर कृषक संगोष्ठी का आयोजन ग्राम फरेदा में आयोजित किया गया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. शेखर सिंह बघेल ने माटी की बेहतर प्रबंधन, नरवाई जलाने से होने वाली समस्याएं जैसे मिट्टी की गुणवत्ता, सूक्ष्मजीवों की कमी, जैव विविधता का नुकसान एवं फसल उत्पादन में होने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कृषि अभियांत्रिकी विभाग की उपसंचालक कृषि अभियांत्रिकी श्रीमती शायला नाज कुरैशी ने कृषि यंत्रों की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी किसानों को दी।

कृषि विभाग के सहायक संचालक कृषि श्री पवन कौरव द्वारा उर्वरक प्राप्ति हेतु ई टोकन प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया। कृषि इंजीनियर श्री जेएस धुर्वे द्वारा नरवाई प्रबंधन के विभिन्न कृषि यंत्रों के व्यवहारिक उपयोग के विषय में बताया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. निखिल सिंह द्वारा रबी फसलों में समसामयिक प्रबंधन एवं नरवाई का बेहतर प्रबंधन कैसे करें, डॉ राजेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा फसलों का मूल्य संवर्धन एवं प्रोसेसिंग के विषय में जानकारी दी। इंजीनियर कुमार सोनी ने कृषि यंत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार कृषि इंजीनियर श्री धुर्वे द्वारा किया गया। साथ ही ग्राम फरेदा के प्रगतिशील किसान श्री भुजबल सिंह गहलोत एवं अन्य कृषकों द्वारा अपने अनुभव एवं खेती की जानकारी दी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में ग्राम के किसानों एव रावे छात्राओं एवं श्री देवी प्रसाद तिवारी का सहयोग प्राप्त हुआ ।

# Bharat-VISTAAR : क्या खेती में फैसले अब जानकारी के आधार पर होंगे ?

खेती में जोखिम का बड़ा कारण आज भी जानकारी की कमी या देर से मिली जानकारी है। मौसम में अचानक बदलाव, गलत फसल चयन, अनावश्यक दवा छिड़काव और बाजार भाव की अनिश्चितता सीधे किसान की आय को प्रभावित करती है। ऐसे में आम बजट 2026-27 में प्रस्तावित Bharat-VISTAAR प्लेटफॉर्म को एक डिजिटल समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

यह एक AI आधारित कृषि सलाह प्रणाली होगी, जिसका दावा है कि यह किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में मौसम, फसल चयन, कीट-रोग प्रबंधन, खाद-सिंचाई और बाजार भाव से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएगी। यदि यह जानकारी स्थानीय परिस्थितियों और जमीन की वास्तविक स्थिति के अनुरूप रही, तो खेती में अनुमान के बजाय गणना आधारित निर्णय संभव हो सकते हैं।

हालांकि, इसकी सफलता कुछ अहम सवालों पर निर्भर करेगी-क्या छोटे किसानों तक स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच पर्याप्त है, क्या सलाह क्षेत्र-विशेष होगी, और क्या किसान उस जानकारी पर भरोसा कर पाएंगे। यदि ये चुनौतियां हल होती हैं, तो Bharat-VISTAAR खेती में जोखिम घटाने का एक उपयोगी साधन बन सकता है; अन्यथा यह केवल एक सूचना मंच बनकर रह सकता है।

**- मयूर नरेंद्र पाटिल**
**संचालक - वेस्ट निमाड़ एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लि., पानसेमल, जिला- बड़वानी**

78 वर्ष
कृषक जगत
राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल-जयपुर-रायपुर

वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक
- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि
➪ वार्षिक रु. 600/-
➪ दो वर्ष रु. 1000/-
➪ तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से **'कृषक जगत'** – प्रति सप्ताह ☐ भोपाल ☐ जयपुर ☐ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).

नाम .....
.....
ग्राम .....पो. .....
**डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें : .....**
वि.ख. ..... तह. .....
जिला ..... पिन ☐☐☐☐☐☐ राज्य .....
शिक्षा ..... भूमि ..... उम्र .....
ट्रैक्टर/मॉडल ..... फोन/मो. .....
ई-मेल .....
मेरा सदस्यता शुल्क रुपये ..... नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/
मनीऑर्डर/क्र. ..... 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

*कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम*
कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक
http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php
Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793, Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861
कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222

**पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861**
**2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।**

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

**भोपाल** : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org
**जयपुर** : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952
**रायपुर** : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),मो.: 9826255862
**इंदौर** : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864
**नई दिल्ली** : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

# भोपाल कृषि प्रदर्शनी में कोरोमंडल ने की सहभागिता

**इंदौर (कृषक जगत)।** विगत दिनों भोपाल में आयोजित प्रतिष्ठित कृषि प्रदर्शनी में कोरोमंडल इंटरनेशनल लि. ने पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की। इस दो दिवसीय आयोजन में विधायक श्री भगवानदास सबनानी, उप संचालक कृषि श्री सुमन प्रसाद सहित बड़ी संख्या में कृषि विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही।

प्रदर्शनी में कृषि क्षेत्र में नवाचार एवं टिकाऊ विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए, कोरोमंडल

इंटरनेशनल लि. का मुख्य उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक, व्यवहारिक एवं आधुनिक कृषि समाधानों से अवगत कराना रहा। कंपनी ने संतुलित पौध पोषण, सही उत्पाद चयन तथा वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के महत्व पर विशेष बल दिया, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने में सहायता मिल सके। प्रदर्शनी के दौरान कंपनी के उन्नत उत्पाद ग्रो प्लस, ग्रो अल्फा तथा ग्रोमोर नैनो डीएपी को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया। इन उत्पादों की विशेषताओं, उन्नत तकनीक, फसल-विशेष उपयोगिता एवं समय अनुसार प्रयोग विधि को सरल भाषा में समझाया गया। किसानों को बताया गया कि ये उत्पाद मिट्टी की सेहत को बनाए रखते हुए फसल की गुणवत्ता एवं उपज में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सहायक हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी की बल्क उर्वरक उत्पाद श्रृंखला को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। विशेषज्ञों ने किसानों को विभिन्न फसलों की पोषण आवश्यकताओं, संतुलित उर्वरक उपयोग, लागत प्रबंधन तथा दीर्घकालिक मिट्टी स्वास्थ्य के महत्व पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया।

डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में कंपनी की न्यूट्री कनेक्ट मोबाइल ऐप पहल भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध मृदा परीक्षण (स्वॉइल टेस्टिंग) सेवाओं की जानकारी देते हुए किसानों को डिजिटल तकनीक द्वारा मिट्टी की पोषक तत्व स्थिति का वैज्ञानिक विश्लेषण कर संतुलित उर्वरक उपयोग अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। यह पहल पर्यावरण संरक्षण एवं सतत कृषि को भी प्रोत्साहित करती है। प्रदर्शनी में कंपनी का आधुनिक एवं आकर्षक स्टॉल किसानों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। बड़ी संख्या में किसानों ने स्टॉल का भ्रमण किया और कंपनी के कृषि विशेषज्ञों से सीधा संवाद कर आधुनिक खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्राप्त की।भोपाल प्रदर्शनी में कोरोमंडल इंटरनेशनल लि की सहभागिता किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई।

# पांढुर्ना में पाला प्रभावित कपास फसल का किया मौका निरीक्षण

**(उमेश खोड़े, कृषक जगत, पांढुर्ना)।** पांढुर्ना क्षेत्र के किसानों द्वारा गत माह पाले एवं कीट से प्रभावित हुई कपास फसल को लेकर जन सुनवाई में शिकायती आवेदन देकर मुआवजे की मांग की गई थी। करीब एक माह बाद शुक्रवार को राजस्व और कृषि विभाग की टीम ग्राम धावड़ीखापा एवं अन्य गांव में पहुंची और कपास की खड़ी फसल का मौका निरीक्षण कर पंचनामा बनाया गया। लेकिन इस सरकारी लेटलतीफी से किसान नाराज़ दिखे।

उल्लेखनीय है कि पांढुर्ना तहसील के ग्राम धावड़ीखापा, मोरडोंगरी, नीलकंठ आदि गांवों में जनवरी के दूसरे सप्ताह में पड़े पाले और कीट प्रभाव से किसानों की कपास की 60-70 प्रतिशत तक फसल खराब हो गई थी, जिसे लेकर पूर्व मंत्री श्री नानाभाऊ मोहोड़ और भारतीय किसान संघ, पांढुर्ना द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, वहीं किसानों ने कलेक्टर की जन सुनवाई में शिकायत कर मुआवजे की मांग की थी। शिकायत के करीब एक माह बाद राजस्व और कृषि विभाग की टीम शुक्रवार को धावड़ीखापा और नीलकंठ पहुंची और 8-9 किसानों की कपास फसल का मौका निरीक्षण कर पंचनामा बनाया गया।

धावड़ीखापा के किसान श्री प्रकाश चंद्र देशमुख और श्री मंसाराम खोड़े ने कृषक जगत को बताया कि लालिया रोग और कीट प्रभाव से कई किसानों की 60-70 प्रतिशत कपास फसल प्रभावित हो गई, जिससे पैदावार में कमी हुई। जहां पहले 0.4 हेक्टेयर में 12-15 क्विंटल कपास होता था, वह वर्तमान में 3-4 क्विंटल होना पाया गया। किसानों का कहना था कि यदि प्रभावित फसल का समय पर निरीक्षण हो जाता तो फसल क्षति का आकलन सही बैठता, तो मुआवजा भी उचित मिलता। निरीक्षण में विलम्ब से होने से जायद की फसलों में भी देरी हो रही थी। कपास फसल के मौका निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग की ओर से पटवारी श्री पंकज कुमरे एवं कृषि विभाग की ओर से श्री राहुल सरयाम,शिवानी चौरे और शिवानी उइके मौजूद थे। किसानों की इस समस्या को कृषक जगत के 12 जनवरी के अंक में 'पांढुर्ना क्षेत्र में पाले से फसलों को हुआ भारी नुकसान' शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।

## पत्र, संपादक के नाम

# विक्रेताओं को बेचने से पहले कृषि आदान को आजमाना चाहिए

गत दिनों कृषक जगत में शिवपुरी जिले में फफूंद नाशक से चना और मसूर की फसल खराब होने का समाचार प्रकाशित किया गया था। इस विषय को लेकर वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुए। सभी चाहते हैं कि किसान की फसल अच्छी हो और वह समृद्ध हो। लेकिन प्राय: देखा गया है कि थोड़े से पैसों के लालच में या ज्यादा कमाई के चक्कर में हमारे कृषि आदान व्यापारी साथी इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं। किसी भी छोटी-मोटी कंपनियों का कृषि आदान उठाकर अपने प्रतिष्ठान से बिक्री करने लगते हैं। जबकि उनको पहले एक साल उक्त कृषि आदान को आजमाना चाहिए। कुछ किसानों को देकर उसके रिजल्ट लेना चाहिए। स्वयं को किसान के खेत पर जाकर देखना चाहिए कि इस प्रोडक्ट की क्या स्थिति है? इसके परिणाम क्या है ? उसके बाद उसकी बिक्री करना चाहिए।

लेकिन यह विक्रेताओं की कमजोरी है कि किसी भी छोटी-मोटी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट उठाकर अपने प्रतिष्ठान से उसकी बिक्री करते हैं जिसका नतीजा शिवपुरी जिले की घटना के रूप में सामने आता है। अत: हमारा सभी कृषि आदान व्यापारी साथियों से निवेदन है कि अपने प्रतिष्ठान से प्रतिष्ठित अच्छी कंपनियों का ही कृषि आदान अपने किसान भाइयों को दे, जिससे वह भी खुश रहें और आपके प्रतिष्ठान की साख भी बनी रहे। उक्त घटना के समाचार प्रकाशन के लिए हम कृषक जगत समाचार पत्र के आभारी हैं ।

**- कृष्णा दुबे, अध्यक्ष, जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ, जिला इंदौर**

पटवारी एग्रो एजेन्सी
:: वितरक ::
◆ कलश सीड्स लि. ◆ बायोस्टेट इंडिया लि. ◆ बॉयर कॉप साइंस ◆ धानुका एग्रीटेक लि.
◆ एफ.एम.सी. इंडिया प्रा.लि. ◆ घरड़ा केमिकल्स लि. ◆ अतुल एग्रीटेक लि.
◆ रामा फॉस्फेट्स लि. ◆ जी.एन.एफ.सी. ◆ इंसेक्टीसाइड्स इंडिया लि. ◆ बीएएसएफ
◆ डयूपॉन्ट इंडिया लि. ◆ क्रिस्टल क्राप साइंस ◆ डाउएग्रो साइंसेस ◆ एग्री सर्च इंडिया
◆ मंशा इंडिया लि. ◆ स्वाल कार्पोरेशन लि. ◆ मेघमनी आर्गेनिक्स ◆ अदामा इंडिया लि.
17, विशाल टॉवर, इंदिरा काम्पलेक्स, नवलखा चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)
फोन : 2403694, 2400412, मो. : 9425077083

कैरा टेक्नोप्लास्ट प्रा.लि., खरगोन
आपकी समृद्धि हमारी प्राथमिकता
हमारे यहां पर ड्रिप में फ्लैट और राउण्ड एचडीपीई व स्प्रिंकलर पाईप, एचडीपीई क्वाइल, लपेटा पाईप एवं रेन पाईप वर्जिन एवं उच्च क्वालिटी में बनाये जाते हैं। सम्पर्क - निरंजन नगर, कसरावद रोड, खरगोन, मो. : 7880017028, 7880017021
मई 25

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरी
ISO 9001 : 2015 सर्टिफाईड
किसान हाईटेक ग्रीनहाऊस नर्सरी
द्वारा पपीता, मिर्च, टमाटर, बैंगन, तरबूज, करेला, पत्तागोभी, फूलगोभी आदि सब्जी के पौधे टेबल स्टेण्ड के ऊपर रखकर तैयार किए जाते हैं
सम्पर्क : 9407361901, 9407361902, 9407361903
सहयोगी प्रतिष्ठान : बागवानी बाजार नर्सरी
जहां पर फलदार, सजावटी व फारेस्टी पौधों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। संपर्क : मो. : 9407853117, 9407853118, 9407853119, नर्सरी स्थल : ग्राम-सिरलाय, तह.- बड़वाह 451115, जिला-खरगोन (म.प्र.)
मार्च 25

कई प्रकार की फसलों के लिए एकमात्र स्वचलित गियर ड्राईव
वरदान
मल्टीक्रॉप पॉवर रीपर
वरदान एग्री सॉल्यूशन्स प्रा.लि.
63, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर-452015 (म.प्र.) फोन: 0731-4970600, 6264916090.

TerraGlebe Farmers Producer Company Limited
NIMADFRESH
यूरोप में मिर्च निर्यात (एक्सपोर्ट) करने वाला मध्यप्रदेश का पहला किसान उत्पादक संगठन बना 'टेरागलेब'
अब उसी की तर्ज पर नाबार्ड से गठित FPO निमाड़फ्रेश FPO रसायन मुक्त मसाले का बना मैन्युफैक्चर ODOP - मिर्च-खरगोन
निमाड़फ्रेश FPO (JV) हरिओम भूरे 8964087240
टेरागलेब FPO बालकृष्ण पाटीदार 9575524408
जुलाई 26

मध्यभारत की सबसे बड़ी नर्सरी
तिरुपति ग्रीन हाऊस नर्सरी
देश का सबसे बड़ा पौध भंडार औषधीय, फलदार, सजावटी फूलों के पौधे, इनडोर, टिश्यूकल्चर, क्रीपर, बोन्साई, सक्यूलेन्ट्स, केक्टस, हैंगिंग प्लांट, वर्टीकल प्लांट, लकी बैंबू रेंज, फॉरेस्ट्री प्लांट एवं सब्जियों के पौधों की विस्तृत श्रृंखला में
: आपका स्वागत है :
सिरलाय (बड़वाह) मध्यप्रदेश
www. tirupatinursery.com
email : tirupatinursery@gmail.com
मो. : 9479457720/99/63/86/96/16/17/13/31/51
मार्च 2025

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ
व्यक्तिगत क्लासीफाइड
विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-
- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि ■ बीज ■ औषधीय फसल
विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक ■ अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक
डिस्प्ले क्लासीफाइड
विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण जीएसटी 5%अतिरिक्त
साइज : फिक्स साइज- 8 × 5 = 40 वर्ग से.मी.
कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रेक्ल्स, तीर्थ यात्राएं, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।
कृषक जगत
की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.
62 62 166 222
www.krishakjagat.org @krishakjagatindia
@krishakjagat @krishak_jagat

## इंडियन माइक्रोन्यूट्रिएंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने उठाया

# 'वन नेशन, वन लाइसेंस' का मुद्दा

**मुंबई (कृषक जगत)।** इंडियन माइक्रोन्यूट्रिएंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन (IMMA) ने मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में आयोजित 6वें राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन एवं बी2बी एक्सपो का सफल आयोजन किया। सम्मेलन में नीतिगत सुधार, मृदा स्वास्थ्य और नियामकीय समन्वय प्रमुख विमर्श के विषय रहे।

'कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को-क्रिएट' थीम के तहत आयोजित दो दिवसीय इस सम्मेलन में नीति-निर्माताओं, नियामकों, वैज्ञानिकों, राज्य कृषि नेतृत्व तथा कृषि-इनपुट निर्माताओं ने भाग लिया। चर्चा का केंद्र भारत के फसल पोषण तंत्र को सुदृढ़ करने और कृषि-इनपुट क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने पर रहा।

सम्मेलन का उद्घाटन श्री जयकुमार जितेंद्रसिंह रावल, मंत्री (मार्केटिंग एवं प्रोटोकॉल), महाराष्ट्र सरकार ने किया। डॉ. पी. के. सिंह, कृषि आयुक्त, भारत सरकार, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ICAR, राज्य कृषि विभागों, विभिन्न

राज्यों के कृषि आयुक्तों तथा प्रमुख कृषि-इनपुट कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने नीतिगत संवाद और तकनीकी सत्रों में भाग लिया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. पी. के. सिंह ने सतत कृषि विकास के लिए मृदा स्तर पर हस्तक्षेप के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संतुलित पोषण और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत कम करने, क्षतिग्रस्त भूमि को पुर्नस्थापित करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

श्री जयकुमार जितेंद्रसिंह रावल ने पिछले चार दशकों में माइक्रोन्यूट्रिएंट और विशेष उर्वरक उद्योग के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस उद्योग ने फसल उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने किसानों, बीज उद्योग, उर्वरक एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट निर्माताओं तथा कटाई के बाद प्रसंस्करण क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि एक एकीकृत कृषि मूल्य श्रृंखला का निर्माण हो सके। उन्होंने MSME आधारित उद्योगों के प्रति महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि अनुसंधान, विकास और नवाचार में निरंतर निवेश से ही भारत 2047 तक वैश्विक कृषि-इनपुट विनिर्माण में नेतृत्व प्राप्त कर सकता है।

सम्मेलन का एक प्रमुख नीतिगत निष्कर्ष 'वन नेशन, वन लाइसेंस' की दिशा में उद्योग की दोबारा उठाई गई मांग रही। इसके तहत राज्य सरकारों द्वारा विपणन अनुमति के लिए उपयोग किए जा सकने वाले केंद्रीकृत लाइसेंसिंग डेटा स्टैक की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

IMMA ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रगतिशील किसानों को फसल-विशेष नवाचार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया, जिससे खेत स्तर पर माइक्रोन्यूट्रिएंट आधारित हस्तक्षेपों की भूमिका को रेखांकित किया गया।

सम्मेलन के दौरान IMMA पिच पार्टी का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्टार्टअप्स और स्थापित कंपनियों द्वारा 16 नवीन फसल पोषण और कृषि-इनपुट उत्पाद प्रस्तुत किए गए।

IMMA के अध्यक्ष डॉ. राहुल मिर्चंदानी ने कहा कि संगठन ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक केंद्रीकृत लाइसेंसिंग डेटा रिपॉजिटरी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे राज्य सरकारें एक सामान्य सर्वर के माध्यम से एक्सेस कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि इससे बार-बार होने वाले अनुपालन को कम किया जा सकेगा, जबकि नियामकीय निगरानी बनी रहेगी, और 'वन नेशन, वन लाइसेंस' को व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि IMMA ने ICAR के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सदस्यों के लिए नियमित तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे।

# कीटनाशकों पर आयात शुल्क 5% करने की मांग

**नई दिल्ली (कृषक जगत)।** ACFI – एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI) ने सरकार से आग्रह किया है कि भारत में कीटनाशकों पर आयात शुल्क को मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए। संगठन का कहना है कि इससे किसानों की खेती लागत कम होगी और उन्हें नई एवं प्रभावी फसल सुरक्षा तकनीकों तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।

सरकार को सौंपे गए अपने ज्ञापन में ACFI ने फसल सुरक्षा रसायनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों के युक्तिकरण की भी मांग की है।

ACFI के अनुसार, पिछले एक दशक में सरकार ने कृषि और किसानों के समर्थन के लिए कई योजनाएं और सुधार लागू किए हैं, जिनमें सब्सिडी, इनपुट सपोर्ट, ऋण सुधार, डिजिटल अवसंरचना और कृषि विपणन से जुड़े कदम शामिल हैं। संगठन का मानना है कि कुछ अतिरिक्त नीतिगत उपाय किसानों को और अधिक लागत-प्रभावी खेती करने में मदद कर सकते हैं।

ACFI ने कहा कि किसान खेती के लिए बीज, उर्वरक, सिंचाई, श्रम और अन्य इनपुट्स पर बड़ी राशि निवेश करते हैं। ऐसे में कीटनाशक फसलों को कीट और रोगों से बचाने में एक प्रकार की सुरक्षा भूमिका निभाते हैं। बदलते फसल पैटर्न और कृषि-जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को नए और प्रभावी उत्पादों की व्यापक उपलब्धता आवश्यक है।

**एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक डॉ. कल्याण गोस्वामी** ने कहा, 'हम आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का सुझाव देते हैं, ताकि किसानों तक नई तकनीकों का वास्तविक लाभ पहुंच सके। यह निर्णय भारत की समग्र कृषि रणनीति के संदर्भ में लिया जाना चाहिए।'

उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट्स उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

ACFI ने कृषि इनपुट्स पर मौजूदा GST संरचना पर भी ध्यान दिलाया। जहां उर्वरकों पर 5 प्रतिशत GST लगाया जाता है, वहीं कीटनाशकों पर 18 प्रतिशत GST लागू है। संगठन के अनुसार, यह अंतर खेती की लागत को बढ़ाता है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए।

भारत में 85 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है। ACFI का कहना है कि ऐसे किसान पहले से ही सीमित वित्तीय संसाधनों और सब्सिडी तक सीमित पहुंच की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कीटनाशकों पर अधिक GST सीधे तौर पर उनकी लागत बढ़ाता है और आवश्यक फसल सुरक्षा समाधानों को अपनाने में बाधा बनता है।

डॉ. गोस्वामी ने कहा कि उर्वरक और कीटनाशक दोनों ही फसल उत्पादन और उपज सुरक्षा के लिए आवश्यक इनपुट हैं। ऐसे में इन पर अलग-अलग और असमान GST दरें बनाए रखना नीतिगत असंगति को दर्शाता है।

# धानुका किसान सम्मेलन में जल प्रबंधन और टिकाऊ खेती पर जोर

**मुज़फ्फरपुर (कृषक जगत)।** 'बिहार की कृषि, भारत का भविष्य – विकसित भारत 2047' विषय पर धानुका एग्रीटेक लि. द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती और किसानों की आय वृद्धि को लेकर व्यापक मंथन हुआ। जिसमें लगभग 450 प्रगतिशील किसानों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी ने कहा कि प्रभावी जल प्रबंधन के बिना कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता संभव नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न किसान कल्याण योजनाओं की जानकारी भी किसानों को दी।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. गोपाल त्रिवेदी ने कृषि अनुसंधान और किसानों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई। वहीं धानुका एग्रीटेक के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. पी. के. चक्रवर्ती ने संतुलित कृषि आदानों और पर्यावरण-अनुकूल पद्धतियों पर जोर दिया।

आईसीएआर-अटारी, पटना के निदेशक डॉ. अंजनी कुमार ने कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों और तकनीक के बीच सेतु बताया।

RPCAU के कुलपति डॉ. पुण्यव्रत सुविमलेन्दु पांडेय ने कहा कि बिहार में फसल विविधीकरण और मूल्य श्रृंखला विकास की अपार संभावनाएं हैं।

तकनीकी सत्र में धानुका एग्रीटेक लि. ने राज्य की कृषि परिस्थितियों के अनुरूप फसल सुरक्षा समाधान प्रस्तुत किए। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट श्री अनुपम पाल ने कहा कि धानुका नवाचार, गुणवत्ता और मजबूत फील्ड सपोर्ट के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कंपनी के मूल मंत्र- 'धानुका का प्रणाम, हर किसान के नाम' को भी रेखांकित किया। सम्मेलन ने बिहार की कृषि में नवाचार और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में राज्य की भूमिका को सशक्त रूप से रेखांकित किया।

**कृषक जगत की सदस्यता हेतु संपर्क करें**

**शैलेन्द्र फरक्या,** बलराम एंड ब्रदर्स, पिपलिया मंडी, जिला- मन्दसौर, मो. : 9893189345
**सतीशचन्द्र शर्मा,** मे. शर्मा एग्रो एजेन्सी, पनवाड़ी, जिला-शाजापुर, मो. : 9893296531
**विशाल पाटीदार,** मे. गायत्री कृषि एवं बीज भंडार, शुजालपुर मंडी, मो. : 8120700900

## खेती में मशीनीकरण की रफ्तार तेज

# CNH-न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर ने भारत में बढ़ाई तैयारी



**( निमिष गंगराडे )**

**भारत की खेती में ट्रैक्टर आज भी सबसे अहम मशीन बना हुआ है। जुताई, बुवाई, ढुलाई और अनेक कृषि कार्य इसके बिना पूरे नहीं हो पाते। इसके बावजूद, पिछले कुछ वर्षों तक देश में ट्रैक्टर बाजार सालाना 10 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार नहीं कर सका। किसानों को जरूरत तो थी, लेकिन ऊँची कीमतें और नीतिगत कारणों से खरीद के निर्णय अक्सर टलते रहे। अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर जीएसटी ढांचे की समीक्षा के बाद वर्ष 2025 में भारत में ट्रैक्टरों की कुल बिक्री 10.90 लाख यूनिट तक पहुंच गई। यह स्पष्ट संकेत है कि खेती में मशीनीकरण की रफ्तार एक बार फिर तेज हो रही है।**

इसी बदलते माहौल में सीएनएच (CNH)- जो न्यू हॉलैंड (New Holland) ट्रैक्टर बनाती है- ने भारतीय बाजार में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है। वर्ष 2025 में कंपनी ने 48,642 ट्रैक्टर बेचे, जो 2024 की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक हैं। इसके साथ ही कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 4.46 प्रतिशत तक पहुंच गई। जहां पूरे ट्रैक्टर उद्योग की वृद्धि दर 2025 में लगभग 20 प्रतिशत रही, वहीं सीएनएच इंडिया ने 27 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। इस तेजी के पीछे सरकारी नीतियों का समर्थन, डीलर नेटवर्क का विस्तार, प्रतिस्पर्धी कीमतें और खेतों में मशीनों की बढ़ती जरूरत जैसे कारण प्रमुख रहे। कंपनी ने अब स्पष्ट लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक सालाना एक लाख ट्रैक्टर बिक्री का आंकड़ा हासिल किया जाए। खेती में मजदूरों की कमी और समय पर कृषि कार्य पूरा करने की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए कंपनी को भरोसा है कि आने वाले वर्षों में ट्रैक्टर की मांग और तेज़ होगी।

### पुणे प्लांट: जहां बनते हैं New Holland ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि समाधान

सीएनएच (CNH) की इस रणनीति की मजबूत नींव कंपनी की पुणे स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। लगभग 2,80,000 वर्ग मीटर में फैले इस प्लांट में डिजाइन, इंजीनियरिंग और उत्पादन की पूरी प्रक्रिया एक ही परिसर में संचालित होती है। यहीं न्यू हॉलैंड (New Holland) ब्रांड के ट्रैक्टर तैयार किए जाते हैं, जिन्हें देशभर के किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्लांट में ट्रैक्टरों के साथ कंबाइन हार्वेस्टर, गन्ना हार्वेस्टर, स्मॉल स्क्वायर बेलर, हेडर, कैब और अन्य कृषि उपकरण भी निर्मित किए जाते हैं। आधुनिक असेंबली लाइन, पेंट शॉप और अत्याधुनिक टेस्टिंग सुविधाओं के माध्यम से यहां ऐसी मशीनें तैयार की जाती हैं, जो भारतीय खेती की परिस्थितियों के अनुरूप हों। यहां निर्मित कई उपकरणों का निर्यात भी किया जाता है।

### ट्रैक्टर से आगे: फसलों के हिसाब से मशीनों पर जोर

हालांकि ट्रैक्टर खेती की रीढ़ हैं, लेकिन सीएनएच अब खुद को केवल ट्रैक्टर तक सीमित नहीं रखना चाहती। कंपनी ने अपना फोकस 'क्रॉप सॉल्यूशंस' पर बढ़ाया है, खासकर उन कृषि कार्यों में जहां मजदूरों की कमी सबसे अधिक महसूस की जाती है।

**सीएनएच इंडिया के प्रेसिडेंट एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नरिंदर मित्तल** के अनुसार, 'ट्रैक्टर के साथ-साथ हम फसलों के अनुसार मशीनें विकसित कर रहे हैं। भारतीय खेती की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेलर और गन्ना हार्वेस्टर तैयार किए जा रहे हैं, ताकि कम मजदूरों में कटाई हो सके और खेत में होने वाला नुकसान घटे।' कंपनी का दावा है कि गन्ना हार्वेस्टर फसल को जमीन के अधिक पास से काटते हैं, जिससे कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम होता है। इससे 5 से 10 प्रतिशत तक उपज बढ़ने में मदद मिल सकती है।

### हार्वेस्टर और बेलर सेगमेंट में किसानों की बढ़ती पसंद

क्रॉप सॉल्यूशंस पर इस फोकस का असर बिक्री के आंकड़ों में भी साफ दिखता है। वर्ष 2025 में सीएनएच ने भारत में 510 हार्वेस्टर और 741 बेलर बेचे। इसके साथ ही हार्वेस्टर और बेलर सेगमेंट में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी करीब 60 प्रतिशत तक पहुंच गई। कंपनी ने वर्ष 2023 में TREM-V मानकों के अनुरूप गन्ना हार्वेस्टर भी पेश किया था, जो नए उत्सर्जन नियमों के अनुसार विकसित किया गया है। किसानों के बीच अपनी पहचान और भरोसा मजबूत करने के लिए सीएनएच ने 2025 में क्रिकेटर युवराज सिंह को ब्रांड एंबेसडर बनाया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से सीधा जुड़ाव स्थापित किया जा सके।

### आने वाले समय की तैयारी

खेती में मशीनों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए सीएनएच ने भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है। कंपनी ने 2028 तक चौथा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने की घोषणा की है। जैसे-जैसे खेती में समय की कमी, मजदूरों की उपलब्धता और लागत का दबाव बढ़ रहा है, ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनें किसानों की अनिवार्य जरूरत बनती जा रही हैं। इसी बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर बनाने वाली सीएनएच (CNH) भारत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है।

**सर्वोत्तम गुणवत्तावाली जैन ड्रिप की विस्तृत उत्पादन श्रृंखला - सभी फसलों # के लिए हर किसान के बजट के अनुरूप विभिन्न प्रकार के ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के विकल्प स्टॉक में उपलब्ध हैं।**

(# दलहन, धान, तिलहन, सब्जियाँ एवं फल बागानें आदि के लिए)

**जैन टर्बो स्लिम - टीई व सुपर सेव्हर**
5 से 20 मील (0.13 से 0.5 मिमी)
**साईज** - 12, 16, 20 मिमी



**जैन टर्बो एक्सेल प्लस**
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
**साईज** - 12, 16, 20 मिमी



**जैन टर्बो लाईन सुपर**
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
**साईज** - 12, 16, 20 मिमी साईज



**जैन टर्बो लाईन - पीसी**
क्लास २
**साईज** - १६, २० मिमी

**जैन टर्बो टॉप - एचडी पीसी**
१३, १५ मील (०.33, ०.38 मिमी) - क्लास 1 व 2
**साईज** - 12, 16, 20 मिमी



**जैन पॉलीट्यूब एवं ड्रिपर्स**
**साईज** - 12, 16, 20, 25, 32 मिमी

नोट : ड्रिपर्स व ड्रिपलाईन अलग-अलग प्रेशर रेटींग में उपलब्ध

जैन ड्रिप® प्रति बूँद, फसल भरपूर!®
जैन इरिगेशन सिस्टम्स् लि. छोटे छोटे कदम. आसमान छूने का दम!®

**दूरभाष:** 0257-2258011; 6600800
**टोल फ्री :** 1800 599 5000
**ई-मेल:** jisl@jains.com; **वेबसाईट:** www.jains.com

ड्रिपलाईन व फिटींग्ज | ड्रिपर्स | रेनपोर्ट स्प्रिंकलर | स्प्रे हेड व जेटस् | वॉल्व | फिल्टर्स | फिल्ट्रेशन संसाधन | फर्टिगेशन संसाधन | पीव्हीसी पाईप व फिटींग्ज | एचडीपीई पाईप्स व फिटींग्ज | क्विक कनेक्ट पाइप | ऑटोमेशन व कन्ट्रोलर्स

**सावधान! नकल करके ड्रिप बनाने वाले एवं नकली ड्रिप कंपनियों और वितरकों से सतर्क रहें!**